06/2013

सप्रू हाउस पत्र

लातिन अमेरिका और कैरीबियाई (एलएसी) क्षेत्र का राजनीतिक और आर्थिक प्रोफाइल

दत्तेश डी. पारुलेकर

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001

लातिन अमेरिका और कैरीबियाई (एलएसी) क्षेत्र का राजनीतिक और आर्थिक प्रोफाइल

दत्तेश डी. पारुलेकर

लातिन अमेरिका और कैरीबियाई (एलएसी) क्षेत्र का राजनीतिक और आर्थिक प्रोफाइल

प्रथम प्रकाशन, 2013

प्रतिलिप्यधिकार © विश्व मामलों की भारतीय परिषद्.
आईएसबीएन : 978-93-83445-01

सभी अधिकार सुरक्षित हैं। इस प्रकाशन का कोई भी भाग कॉपीराइट स्वामी की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना , पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग, या अन्यथा प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में तथ्यों और विचारों की जिम्मेदारी विशेष रूप से लेखक के साथ है और उसकी व्याख्या , विश्व मामलों की भारतीय परिषद , नई दिल्ली के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्,
बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110 001, भारत
दूरभाष. : +91-11-23317242, फैक्स: +91-11-23322710
www.icwa.in

मुद्रण:
एल्फा ग्राफ़िक्स
6A/1, गंगा चैम्बर्स, डबल्यू.ई.ए., करोल बाग. नई दिल्ली -110005
दूरभाष : 9312430311
ई-मेल : tarunberi2000@gmail.com

विषय - सूची

लातिन अमेरिका की स्वतंत्रता के उपरांत राजनीति और राजनीतिक स्थापना का उद्भव

आर्थिक विकास रणनीतियां- लातिन अमेरिका के सांचे पर 'आईएसटी.एवं 'वांशिगटन समझौता'

समकालीन लातिन अमेरिका में 'वामपंथ' को लातिन अमेरिका में 'चीन' - दि इकानॉमिक्स ऑफ इट ऑल

लातिन अमेरिका में पेट्रो-राजनीति और बदलते शक्ति के संबंध

वैश्विक स्थान में लातिन अमेरिका

लातिन अमेरिका और कैरीबियाई (एलएसी) क्षेत्र का राजनीतिक और आर्थिक प्रोफाइल

'लातिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र' अभिव्यक्ति, जिसका सूत्रीकरण अपने-आप में ही कतिपय विवाद का विषय रहा है, तथा जिसका सर्वप्रथम, अपने भौगोलिक महत्व से कुछ अधिक महत्व है, जहां तक यह रियो ग्रेंडे के दक्षिण स्थित समस्त प्रादेशिक एककों की ओर संकेत करती है जिसमें लातिन (स्पैनिश, पुर्तगाली और फ्रांसीसी) से ली गई भाषा प्रचलन में है। ऐसी परिभाषा के दृष्टिकोण से इसका एकमात्र आश्वस्त श्रेय पश्चिमी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति तथा उनकी भाषाओं के उद्गम को दिया जा सकता है जो क्षेत्र समस्त देशों के लिए साझा है। आकार, जनसंख्या नृजातीयता, प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु और/अथवा विकास के मापन के होते हुए भी, देशों में विभेद करने को उतना ही युगीय समझा जाता था जितने कि वे देश थे जिनके साथ उनके साझे हित होते थे। एलएसी क्षेत्र जिसमें तीन मुख्य उप-क्षेत्र हैं अर्थात् दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, मध्य अथवा मेसो-अमेरिका, जो मेक्सिको से पनामा तक फैला है तथा कैरीबियाई क्षेत्र, 33 पृथक देशों के भौगोलिक विस्तार को शामिल करता है जो कैरीबियाई क्षेत्र के छोटे द्वीप राज्यों से लेकर ब्राजील और अर्जेंटीना आदि जैसे बड़े क्षेत्रीय खंडों तक फैला है, तथा जो नस्लीय, नृजातीय, भाषायी, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में परस्पर गुंथा है।

इसके बावजूद, इस तथ्य का कोई विरोध नहीं है कि भौगोलिक और भाषायी तथ्यों से जुड़े गणराज्य साझे उपनिवेशी अनुभवों से आपस में बंधे होते हैं, जहां तक स्पेन और पुर्तगाली साम्राज्यों से तत्कालीन विभाजन शामिल हैं जो उन्नीसवीं शताब्दी से ही नए स्वतंत्र हुए गणराज्यों के आर्थिक और राजनीतिक उतार-चढ़ावों से साझे होते हैं। उस सीमा तक, विकास के अनसुलझे पैटर्न जो ऐसे उत्पादन में उलझे रहते हैं, और जो अधिक समृद्ध हो चुके औद्योगिक उपनिवेश देशों को प्राथमिक वस्तुओं और प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण करते हैं, और इसाझे अतीत की भावना को साझा करते हैं। जो 'लातिन अमेरिका' अभिव्यक्ति के प्रमाणिक अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वे इस दिशा में अफ्रीका, एशिया और यूरोप में साथी देशों के स्थान पर ऐसे क्षेत्रों को उजागर करते हैं जो अधिक संसक्त रूप से बंधे हुए हैं। लातिन अमेरिकी मित्र-देश, अत्यंत कम संभावित रूप से विकृत करने वाले सीमावर्ती परिवर्तनों, संबंध-विच्छेदी विद्रोहों अथवा

संलग्न करने वाले प्रयासों, पूर्वज, प्रत्यावर्ती अंतर्राज्यीय विवादों को हवा देने और उन्हें भड़काने के संबंध में अन्य स्थानों की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से स्थिर रहे हैं।

लातिन अमेरिका का गठन करने वाले देशों में दक्षिण अमेरिका के 10 गणराज्य शामिल हैं जिनमें गुयाना की तिकड़ी, पनामा सहित मध्य अमेरिका अमेरिका के छह गणराज्य भी आते हैं परंतु इसमें बेलिज नहीं है, और साथ ही मेक्सिको, क्यूबा, डोमनियम गणराज्य और हेती भी हैं जिसके इसका योग 20 संप्रभु देश बनता है। स्पेनी भाषा इनमें से 18 भू-भागों में बोली जाती है तथा ब्राजील में प्रथम रूप से पुर्तगाली का दबदबा है तथा हेती में फ्रांस से उपजी 'क्रेयोल' भाषा है। यह माना जाता है कि मेक्सिको, बोलीविया, एक्वाडोर, ग्याटेमाला, परागुए और पेरू में भारतीय भाषाएं प्रचलन में है जबकि लातिन अमेरिका के पट्टियों पर अल्पसंख्यकों के लिए अंग्रेजी पसंदीदा भाषा है। साओ पोलो और लीमा की गलियों में प्रायः जापनी भाषा सुनाई देती है जबकि अनेक गणराज्य चीनी मूल और नस्ल के लोगों की उल्लेखनीय संख्या में उपस्थित पर गर्व करते हैं।

वर्ष 1791 से कैरीबियाई क्षेत्र में अनुबंध पर कार्य करने वाले अफ्रीकी श्रमिकों ने अपने फ्रांसीसी उपनिवेशकों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया तथा 1804 के नए साल तक होती एक नवप्रवर्तक के रूप में उभरकर सामने आया तथा यह क्षेत्र में पहला स्वतंत्र देश बन गया। दूसरी ओर ब्राजील, जो क्षेत्र में सर्वाधिक महंगा देश था, ने 1822 में पुर्तगाली साम्राज्य से स्वदेश राजतंत्र में शांत रूपांतरण हासिल कर लिया था। स्पेनी लातिन अमेरिका की प्रधानता के अंतर्गत स्वतंत्रता की लहर व्याप्त होने के बावजूद इसकी काफी कीमत चुकानी पड़ी। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा शक्तिहीन बनाए जाने के बावजूद भी स्पेनी साम्राज्य बिना किसी संघर्ष के अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मेक्सिको से लेकर चिली तक 'क्रेओल' सेनाओं ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हथियारों के बल पर स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। वे काफी हद तक अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा प्रेरित थे तथा स्पेनी साम्राज्य की कमजोरी से जानकार थे और अनेक मामलों में स्पेन-विरोधी (मुख्यतः ब्रिटिश) सैनिकों द्वारा समर्थन हासिल कर रहे थे। अधिकांश अंग्रेजी-भाषी कैरीबियाई राज्यों ने बीसवीं शताब्दी में ही अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। मार्टिनिक और ग्वाडालोपे के कैरीबियाई द्वीपों तथा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में फ्रेंच गुयाना फ्रांसीसी भू-भाग बने रहे। डच ऐन्टिली को उनके योगदान के लिए पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है, परंतु वे अभी भी बजट के लिए तथा बाहरी हस्तक्षेप और

परिवर्तनके लिए नीदरलैंड्सपर आश्रितहैं।

बीसवीं शताब्दीमें लातिनअमेरिकीराष्ट्रों ने तीसरे विश्व के देशों के समस्याओं को साझा किया, जो आर्थिक विकास तथा अधिक शक्तिशाली आर्थिक समाजों के साथ संबंधों से जुड़ी हुई थी। लातिन अमेरिका की पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता तथा उसकी पश्चिम द्वारा प्रभावितराजनीतिकऔर सामाजिकसंरचनाएं अवांछनीयविशेषताओं से परिपूर्ण थी। उनकी अर्थव्यवस्थाएंपश्चिमी निवेश और निर्यातों पर निर्भर होने के कारण विश्व प्रणालीमें विद्यमानविकृतियोंऔर उतार-चढ़ावोंके प्रति संवेदनशीलथीं। आर्थिक निर्भरता राष्ट्रीयजीवन में राजनीतिकऔर सांस्कृतिक निर्भरता के साथ हावी हो गई थी। लातिन अमेरिकियों ने या तो विदेशी विचारधाराओं को अपनाकर अथवा घरेलू प्रतिक्रियाओं को तैयार करते हुए सामाजिकन्याय, सांस्कृतिक स्वायत्तता और आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि कृषि और खनिज उत्पादन जारी रहा, औद्योगिक विकास ने श्रमिक संगठन, आप्रवासनऔर शहरी विकास में वृद्धि कर दी थी। राजनीतिकप्रक्रिया में शामिल होने के लिए शहरी मध्यम वर्ग का अभ्युदय हो गया। आर्थिक विस्तार और राजनीतिकयथास्थितिका परिरक्षणसंकट की अवधियोंके साथ परिवर्तित हुआ जब राजनीतिक पैटर्नों को तोड़ने और सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए। सतही परिवर्तनोंके बावजूद लातिन अमेरिका तुलनात्मकरूप से अपरिवर्तितरहा क्योंकि पुरानी संस्थाओं ने नए प्रभावों को अपना लिया था। अत्यंत कम क्रांतियों के फलस्वरूपमहत्वपूर्ण राजनीतिकपरिवर्तन आए परंतु सामाजिक और आर्थिक मामलोंमें उल्लेखनीयबदलावविद्यमानथे।

यह अत्यंत दयनीयस्थिति है कि आर्थिक विकास के साथ लातिन अमेरिका का अनुभव अत्यंत निराशाजनकरहा है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी गोलार्ध में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के समान स्तरों पर होने और लगभग उसी समय स्वतंत्रता हासिल करने के बावजूद लातिन अमेरिका और कैरीबियाईक्षेत्र के राष्ट्र अमेरिका और कनाडा से आर्थिक निष्पादनके संदर्भ में तेजी से पिछड़ गए। लातिन अमेरिका ने उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान प्रति व्यक्ति जीडीपी के संदर्भ में किसी भी वृद्धि का अनुभव नहीं किया था, जो ऐसी अवधि थी जिसके दौरान प्रति व्यक्ति जीडीपी चार से छह गुना बढ़ गई थी। हालांकि, लातिन अमेरिका महामंदी के आरंभ होने के बाद से सुदृढ़ आर्थिक विकास का अनुभव करने में समर्थ रहा था, अस्सी के दशक ने समस्त क्षेत्र को अत्यंत मंद और दीर्घकालिकसूक्ष्म आर्थिक संकट की अवधि में

डाल दिया था जिसके फलस्वरूपउसकी विकासदरों में गिरावटआई थी।

लातिन अमेरिका के विकास का प्रदर्शन इतना खराब क्यों हुआ, इस बात की व्यवहार्य समझ इसकी राजनीतिको समझे बिना कदापि संभव नहीं है। लातिन अमेरिका के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विवाद के उच्च स्तरों ने स्वतंत्रता के बाद से इसके आर्थिक विकास को गंभीर रूप से बाधित किया है जिसने मानवीय और भौतिक पूंजी में निवेश के उच्च स्तरो की प्राप्ति में गतिरोध उत्पन्न किया है, जिसके फलस्वरूप इसके प्राकृतिक संसाधनों की विकृति हुई है। इसे किसी क्षेत्र के असंतोषजनकआर्थिक प्रदर्शन और प्रोफाइल के लिए कारण नहीं माना जा सकता है, परंतु इसे राजनीति के परिवर्तनके रूप में कहा जा सकताहै। उदाहरणके लिए, किसी क्षेत्र का शेष विश्व के संबंध में पृथक्कीकरणअन्य क्षेत्रों की विशेषज्ञतासे लाभ उठाने की प्रक्रिया में शामिल होने की उसकी योग्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित और बाधित कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का अभाव घरेलू उद्योगों का विकास करने और साथ ही निर्यात राजस्व के उल्लेखनीयस्रोत हासिल करने की देश की योग्यता को बाधित कर सकता है। सांस्कृतिक मूल्य और धार्मिक आस्थाएं कुशल आर्थिक संस्थाओं के विकास के लिए अधिक अथवा कम मात्रा में अनुकूल हो सकती है। अस्थिरता बाहरी कारकों का परिणाम हो सकती है जैसे व्यापार अथवा बाहरी विवाद की विशेष रूप से अस्थायी शर्तें। इन आगामी अवसरोंमें से अधिकांश पर लातिन अमेरिका तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर था और भली-भांति अवस्थितथा। लातिन अमेरिका की भौगोलिकस्थिति ने इसे एशिया और ओशीनियाकी तुलना में विश्व व्यापार केन्द्रों के समीप रखा हुआ था। पिछली दो शताब्दियोंके दौरान लातिन अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों के मुख्य निर्यातकों में से एक था तथा इसने यह विश्व के किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के दौरान बाहरी विवादों और आक्रमणों से निर्विवाद रूप से कम प्रभावित था। कौन से देश क्षेत्र के दीर्घकालिकअवरुद्धआर्थिक प्रोफाइलको प्रभावितकर रहे थे?

यदि ऐसे कोई कारक विद्यमानहै जिसने उपनिवेशवादकाल के दौरान लातिन अमेरिका की निर्णय लेने की प्रक्रिया को व्याप्त बनाया, वह प्रांतीय प्राधिकारियों और स्थायी हितबद्धसमूहों के बीच विद्यमान विवाद था जिसने स्थानीय भू-स्वामी प्रबुद्ध वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व किया और नौकरशाही को केंद्रीयकृत किया तथा उसे स्थापित किया ताकिवह स्पेनी और पुर्तगाली सम्राटोंके हित का प्रतिनिधित्वकर सके। जबकि स्पेन के सम्राटों का उपनिवेशोंमें वायसरॉयद्वारा और अधिक महत्वपूर्ण रूप से

उपनिवेशीन्यायालयों(दर्शककक्षों) द्वारा प्रतिनिधित्वकिया जाता था, जिनकी स्थापना प्रांतों में सुदृढ़ न्यायिक और कार्यकारिणी संबंधी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सम्यक रूप से की जाती थी, इनका प्राय: कृषकों और खनिजों द्वारा समान रूप से जोरदार और गहन विरोध किया जाता था। इनका एक उदाहरणएनकोमीएन्डाद्वारा निर्मित किए गए गहन राजनीतिक विवाद हैं, जो एक ऐसी प्रणाली थी जिसके द्वारा उपनिवेशकोंको बड़ी संख्या में भारतीयको ईसाईधर्म और 'सभ्य' आचरण के शिक्षण का कार्य सौंपा गया था तथा इसके साथ-साथ यह निर्धारित करने की शक्ति भी दी गई थी कि उनके श्रम का आबंटन किस प्रकार किया जाएगा।वर्ष 1542में, स्पेन के सम्राट ने इंडीज सरकार के लिए कानून और अध्यादेश प्रख्यापित किए जिसमें अमेरिका में शाही प्रशासकों द्वारा नए एनकोमीएन्डाको जारी करने से इंकार किया गया था तथा विद्यमान एनकोमीएन्डाकी विरासत को आरक्षित करने का आदेश दिया गया था। तथापि, एक उपनिवेशी विद्रोही जिसने 1546में पेरूवियनवायसरायको पद से हटा दिया था, ने सम्राट को नए कानूनों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिबंधों को वापस लेने के लिए विवश कर दिया था। महानगरोंसे उत्पन होने वाले प्राधिकार के लिए उपनिवेशी सम्मान इतना सीमित था कि उन्होंने सम्राट के प्रावधानोंके प्रत्युत्तर में से एकाटापेरोनो से कम्प्ले' (हम कानून को अपनाते हैं, परंतु उसका पालन नहीं करते हैं) के विचित्र सिद्धांत को आमतौर पर प्रयोग किया था जिसे वे पसंद नहीं किया करते थे। अत: प्रांतीय सरकारें एक ही समय पर सुदृढ और कमजोर, दोनों ही थीं। कानून और उनके विन्यासों को प्रवर्तित करने की उनकी शक्ति पर्याप्त थी जो भूमि रखने वाले उपनिवेशियोंके हितों में थे परंतु वे स्पेनी सम्राट के आज्ञापत्रको प्रवर्तितकरने में अत्यंत कमजोरथे।

लातिन अमेरिकाद्वारा अपनाईगई आर्थिक संरचना, जो एक उत्पादनसंरचना थी और बागान कृषि पर आधारित थी तथा विभिन्न वर्गों की अर्थव्यवस्थाएं एवं उच्च श्रमिक गहनता इसकी विशेषताएं थीं, का एक विशेष परिणाम बड़ी संख्या में दासों का अंतर्प्रवाह और घरेलू जनसंख्या का श्रमिकों के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग करना था। इसकी तुलना ब्रिटिशउपनिवेशोंके उत्तरीभागों में देखे गए पैटर्नों के साथ की जा सकती है जहां उपनिवेशकअपने श्रमिकों का प्रयोग करने के स्थान पर अपनी भूमियों से वहां के घरेलू लोगों को निष्कासित करने का प्रयास करते थे। इसका परिणाम आय का अत्यंत असमान वितरणथा जिसके दीर्घकालिक परिणाम होने अपेक्षित थे। आर्थिक शक्ति के वितरण ने आर्थिक शक्ति के वितरण को भी प्रतिबिंबित किया हालांकि स्पैनिश

अमेरिका में स्वतंत्रता मोटे तौर पर उस समय आई थी जब ब्रिटिश उपनिवेश स्वतंत्र हुए थे, परंतु लातिन अमेरिका में मतदान के विस्तार को आने में काफी समय लग गया था।

असमानता और पिछड़ापन लातिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की पिछली दो शताब्दियों के दौरान दो केन्द्रीय विशेषताएं रही हैं। क्षेत्र का तिर्यक आय वितरण यूरोपीय यात्रियों को पहले से ही स्पष्ट हो गया था जो उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ होने में स्पेनी उपनिवेशों में पड़ाव डाला करते थे तथा जो अमीरों और गरीबों के बीच आय की असमानता की ओर इशारा किया करते थे। पिछली दो शताब्दियों में क्षेत्र में हुए व्यापक आर्थिक रूपांतरण के बावजूद लातिन अमेरिका में असमानता उसकी एक प्रमुख विशेषता बनी रही। इसी दौरान, लातिन अमेरिका का विकास रिकार्ड उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपनी आय के अंतर को कम करने में अपर्याप्त सिद्ध हुआ जो इस तथ्य का वर्णन करता है कि लातिन अमेरिका 1700 और 1900 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स की तुना में पिछड़ते हुए निर्वासित हो रहा था। उपनिवेशी अमीत से विरासत में ली गई तथा उन्नसवीं शताब्दी में भी लेकर गई असमानता ने लातिन अमेरिका की कराधान की संरचनाओं को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जो न केवल यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की तुलना में पर्याप्ततः भिन्न था बल्कि अन्य विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं से भी अलग था।

उन्नीसवीं शताब्दी की समाप्ति पर तथा आभासी स्थगन के अनेक दशकों के उपरांत लातिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं ने एक धीमी परंतु स्थिर वापसी अनुभव करनी आरंभ कर दी। विकस का प्रारंभ होना वैश्विक अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ घटित हुआ जिसकी एक मुख्य विशेषता पण्यों और कारक बाजारों के विश्वव्यापी एकीकरण के संवर्धन की प्रक्रिया थी। विश्व अर्थव्यवस्था के विस्तारवादी चक्र ने कच्ची सामग्री और खाद्य-पदार्थों के लिए मांग में वृद्धि कर दी जिससे समूचे क्षेत्र में निर्यात क्षेत्र लाभान्वित हुए। तथापि, केवल अर्जेंटीना में ही निर्यात क्षेत्र प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व तीन दशकों के लिए विकास का इंजन बन पाया। स्थिर प्रति व्यक्ति जीडीपी विकास का पुन: आरंभ अनेक कारणों से अन्य देशों में फलीभूत न हो पाया जिसमें कमजोर संस्थाएं, खराब अवसंरचना और गलत तरीके से मार्गदर्शित नीतियां भी शामिल थीं। 1870-1913 की समूची अवधि में, बड़ी संख्या में लातिन अमेरिकी देश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी ऋणों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी अंतर्प्रवाहों के प्राप्तकर्ता बन गए। वास्तविक रूप से प्रत्येक सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से उधार उठाया जिसमें से अधिकांशतः बाह्य ऋण ने रेल-सड़क नेटवर्कों, पत्तन सुविधाओं और सार्वजनिक कार्यों के निर्माण का

वित्त-पोषण किया, इसने लातिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं के बैंकिंग और मुद्रा संकटों को भी उजागर किया। वस्तुतः विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण मूल्यवर्ग संकटों को उत्पन्न किया जहां विदेश ऋण और राजवित्तीय कुप्रबंधन के फलस्वरूप आर्थिक विपत्ति उत्पन्न हो गई थी। यह रुचिकर है कि उभरती और हाशिए पर आई अर्थव्यवस्थाओं के अलावा, जिसमें आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका तथा नार्वे और फिनलैंड जैसे छोटे यूरोपीय देश शामिल थे, सुदृढ़ राजवित्तीय और वित्तीय प्रणालियों ने आवृत्तियों में कमी करने तथा वित्तीय संकटों की उग्रता को कम करने में सहायता प्रदान की।

प्रथम विश्व युद्ध और उसके उपरांत व्यापार और पूंजी के प्रवाहों में आए व्यवधान के परिणामस्वरूप अधिक विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार हुआ और इसी दौरान निर्यात क्षेत्र श्रव्य बाजारों में चक्रीय आंदोलनों से प्रभावित हुआ। लातिन अमेरिका अभी भी बाह्य आघातों के प्रति अत्यंत सुकोमल था तथा महामंदी ने संपूर्ण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में कमी कर दी थी। तथापि, वैयक्तिक परिणाम विविधतापूर्ण थे जो खुलेपन की प्रमात्रा निर्यात मूल्यों के व्यवहार तथा गैर-निर्यात क्षेत्र के वैविध्यीकरण की मात्रा पर आधारित थे। तीस के दशक के प्रारंभ की मंदी से उबरने में रूढिवादी नीतिगत उपायों द्वारा आंशिक मदद की गई थी जिसमें अत्यंत व्यापक वास्तविक अवमूल्ययन और सरकारी व्यय में वृद्धि भी शामिल थी जिन्होंने आयात के विकल्प प्रदान किए तथा सामाजिक विरोधों को शांत किया। द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने के परिणामस्वरूप पण्यों और पूंजी बाजारों में नवीकृत बाह्य अवरोध आए, जिससे क्षेत्र के लिए समग्र रूप से निर्यात आयातों और विदेशी उधारों में और भी कमी आई। चालीस के दशक के अंत में, आर्थिक नीति ने जानबूझकर अनेक देशों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जैसे ब्राजील, मेक्सिको, कोलम्बिया, अर्जेंटीना, चिली और पेरू। इन देशों में, एक विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार तथा एक विशाल घरेलू बाजार ने आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से औद्योगिकीकरण को सहायता प्रदान करने वाले सिद्धांतों को महत्व प्रदान किया।

इस प्रकार, क्षेत्र में विशाल अर्थव्यवस्थाओं ने उत्पादन स्तरों, पूंजीगत नियंत्रणों, मुद्रा नियंत्रणों, बहु मुद्रा दर स्कीमों तथा श्रम बाजारों में जनता के हस्तक्षेप में वृद्धि पर आधारित एक आवक-दर्शी रणनीति का अनुपालन किया। 1950-1960 की अवधि में, 20 विशालतम लातिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए 20 विशालतम लातिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए औसत जीडीपी विकास दर 5.3 प्रतिशत थी। फिर भी, क्षेत्र में

विविधताउल्लेखनीयथी तथा जनसंख्या वृद्धि में हुई तेजी ने प्रति व्यक्ति जीडीपी दरों को कम कर दिया। उदाहरणके लिए, बड़ी अर्थव्यवस्थाओंजैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, मेक्सिको, पेरू और वेनेजुएला में 1950-1973 की अवधि में प्रतिव्यक्ति जीडीपी में वृद्धि का औसत मात्र 2.4 प्रतिशत था। विकास दरों ने व्यापार और पूंजी नियंत्रणों तथा संरक्षणवाद से सहयोजित समस्याओं में वृद्धि की: संसाधनों का अपर्याप्त आबंटन, महंगाई का दबाव, एकाधिकारवाली औद्योगिकसंरचनाएं तथा बढ़ते हुए चालू खाते और सार्वजनिक घाटे। विभिन्न देशों में विभिन्न स्थानों पर बृहद अर्थव्यवस्था व्यवहार के बारे में चिंताएं उभरने लगी, तथा स्थरीकरणकार्यक्रमों ने ऐसे समाधानोंके लिए प्रयास किया जिसमें सफता के विभिन्न अंश शामिल थे। साठवें दशक तक, संयुक्त राष्ट्र लातिन अमेरिका आर्थिक आयोग के तत्वावधान में, आवकन्दर्शी विकास का मॉडल क्षेत्र के वस्तुत: प्रत्येक देश में विद्यमानथा। 1950-1973की अवधि में, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, मेक्सिको, पेरू और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्थाएं 2.4 प्रतिशतकी दर से विकसितहुई जबकि छोटी और कम विविधतापूर्णअर्थव्यवस्थाओं की कहीं कम विकास दर थी। यदि हम देशों के प्रथम समूह पर लातिन अमेरिका के प्रतिनिधियोंके रूप में विचार करें, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल अफ्रीकी देशों की तुलना में ही अधिकथी तथा यह पश्चिमीदेशों के समानथी (आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका)। इस अवधि के दौरान, विश्व के अन्य क्षेत्रों ने अधिक तेज गति के साथ विस्तार किया : एशिया (2.6%)। पूर्वी यूरोप (4.0%) दक्षिणी यूरोप (4.8%) और पश्चिमी यूरोप (3.8%)।

साठ के दशक में, अधिकांश लातिन अमेरिकी सरकारोंने क्षेत्रीय एकीकरणपर आवकन्दर्शी रणनीतियोंमें विद्यमानकतिपयकमियों विशेष रूप से बढ़ते हुए असंतुलनों को दूर करने के उपाय के रूप में विचार किया। फिर भी, विनियममदर, राजवित्तीयऔर मौद्रिक नीतियों के बीच सौहार्द के अभाव के असंतोशजनक परिणाम हुए। अधिक महत्वपूर्ण यह था कि प्रधान तानाशाहीअभिमुखीकरणतथा इसके साथ सहयोजितमूल्य संबंधी विकृतियां अपरिवर्तनीयरहीं। उस समय किसी नीतिगतपरिवर्तनको क्रियान्वित न करने से लातिन अमेरिका के लिए अवसर खो देने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई मूल्यों में विकृतियां सत्तर और अस्सी के दशकों में और अधिक गंभीर हो गई तथा विकृत नीतियों का संचयन और विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। दूसरे अंक्षाशों में, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं औद्योगिकीकृत भी हुई तथा उन्हें समान आवकन्दर्शी रणनीतियों का

अनुपालन किया। विशेष रूप से पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद की अवधि में आयात प्रतिस्थानी औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया जिसमें लातिन अमेरिका में क्रियान्वित की गई नीतियों और उपकरणों के समान ही नीतियां और उपकरण थे। तथापि, साठ और सत्तर के दशक में, पूर्वी एशिया में नीतिगत विचारधारा आवक्-दर्शी विकास से काफी अलग हो गई तथा जावक अभिमुखीकरण की ओर काफी हद तक झुक गई। वैश्विक बाजारों के साथ एकीकरण ने पूर्वी एशिया को नब्बे के दशक तक एक तेजी से बढ़ते विकास को बनाए रखने की अनुमति प्रदान की, जोकि एक ऐसा परिपथ था जो बीसवीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में लातिन अमेरिका के असंतोषजनक आर्थिक विकास रिकार्ड के साथ अत्यंत मिलता-जुलता था।

लातिन अमेरिका की स्वतंत्रता के उपरांत राजनीति और राजनीतिक स्थापना का उद्भव

लातिन अमेरिका को यूरोपियों द्वारा संघीय युग की समाप्ति के उपरांत बसाया गया था, न कि पूर्व पूंजीवाद, उभरते हुए बहुलवाद, प्रबुद्धीकरण और आधुनिकता के काल में, जैसा कि अठारहवीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के मामले में हुआ था। वहां जो अधिकांश लोग बसे थे, जो अंततः अमेरिकी बन गए थे, वे यूरोप में धार्मिक और सामाजिक बाधाओं से भागकर वहां आए थे। उन्होंने वहां छोटे पारिवारिक फार्मों की स्थापना की जैसे नए इंग्लैंड में किया गया था, उनके पास सस्ती भूमि खरीदने के अवसर थे, जैसे-जैसे राष्ट्र पश्चिम की ओर बढ़ते गए। इसकी तुलना में, लातिन अमेरिका में बसने वालों ने स्पैनिश और पुर्तगाली कैथोलिक चर्चों की संस्थाओं की स्थापना की, जो एक कड़ी पदानुक्रम और पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रणाली थी जिस पर विशाल भू-स्वामियों का प्रभुत्व था और वह एक प्राधिकारपूर्ण प्रणाली के अधीन थी। लातिन अमेरिकी राजनीति में पदानुक्रम तथा प्राधिकारपूर्ण व्यवस्था स्वतंत्रता (1810-1830) अथवा उससे भी पूर्व से उद्दीप्त रही है। स्वतंत्रता के उपरांत मध्यवर्ती अर्ध-शताब्दी में, जब क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों जिन्हें 'लॉडिलोस' कहा जाता था, ने अपना प्रभाव दर्शाया तथा स्वयं को दैनिक उतार-चढ़ावों में शामिल कर लिया था, प्रभावी प्रशासन स्थापित करने में होने वाली कठिनाइयों के फलस्वरूप राजनीतिक प्राधिकारी का अपरिहार्य केन्द्रीयकरण हुआ जो राजनीतिक वैधता के साथ सम्मिश्रित हो गया तथा समाज में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्पोरेट प्रकार के राज्य का अनिवार्यतः विकास हो गया (जहां वर्तमान सरकार प्रणाली के भीतर जैसे सेना, भू-स्वामी धनाढ्य वर्ग और बाद में संघ के भीतर अन्य हितधारकों के सहयोग से कार्य करती है)। अर्थपूर्ण

असंतोष और राजनीतिक बहुलवाद के लिए परिणामी स्थूल, अहिष्णुता, यहां अपनी उत्पत्ति के साथ, क्षेत्र में सारवान लोकतंत्रों की स्थापना करने में की गई त्वरित कार्यवाही के बावजूद समकालीन लातिन अमेरिका के असंख्य क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरणा के रूप में अभी भी विद्यमानहै।

पिछले दो दशकों में लातिन अमेरिका में उनके इतिहास के संदर्भ में प्रतिभागी लोकतांत्रिकराजनीतिकसंस्कृति के लिए बढ़ती हुई सहमतिके बावजूद लातिन अमेरिकी देशों की राजनीतिक संस्कृति पर कोई सहमति नहीं रही है। राजनीतिक खेल के कोई पर्याप्त रूप से सहमतनियमनहीं थे। चुनावों को मात्र राजनीतिकशक्ति हासिल करने के एक तरीके रूप में ही देखा जाता था, समाज के कुछ वर्गों में विद्रोहों तथा हिंसक आंदोलनों को समान रूप से वैध माना जाता था। भू-स्वामियों की प्राधिकारपूर्ण और समृद्धि-वर्ग संस्कृति तथाउनके खनन हितों ने लोकतांत्रीकरणकी बढ़ती प्रक्रिया का विरोध किया। उनके मूल्यों का कट्टरवाद(समाजवादीऔर वामपंथी), लोकवाद(जो जनता के हितों को प्रोत्साहित करने की हिमायत करते थे) और यहां तक कि पश्चिमी शैली के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ टकरावहोता था, जिनकी परिकल्पनाऔर निर्माण अस्सी के दशकके बाद कुछ उत्प्रवासियोंद्वारा और समाजके 'मध्यम क्षेत्रों' (जो अशिक्षितगरीब जनता और भू-स्वामियों एवं सामाजिकधनाड्य-वर्गके बीच के लोग थे) द्वारा किया गया था, जिन्होंने प्रतिलोमितभू-स्वामियों और खनन धनाड्यों की शक्ति को कम करने की हिमायत की थी। इसका परिणामअनेक राजनीतिकसंस्कृतियों का सह-अस्तित्व था, जिनमें से कोई भी प्रधाननहीं थी। ये प्रायः आपस में उलझतीथीं और हाल ही तक इन्होंने अनेक लातिन अमेरिकी देशों में राजनीतिक स्थायित्व को जन्म दिया। इसके अलावा, सरकारी अधिकारियोंको रिश्वत देने अपने मित्रों को ठेके प्रदान करने आदि के रूप में राजनीतिक भ्रष्टाचारकी एक सर्वत्र-व्यापी संस्कृति भी विद्यमानथी।

अमेरिका के विपरीत, जहां राजनीतिकसंस्कृति तथा अर्थव्यवस्था(राजनीतिक अर्थव्यवस्था) के साथ राजनीति के संबंध के बारे में सर्वसम्मति राजनीतिक विचारधाराओंकी एक संकीर्ण परिधि उत्पन्न करतीहै जो लातिन अमेरिका में राजनीति को चलातीहै, यह आयाम यहां अत्यंत विपरीतहै। यहां, विखंडितराजनीतिकसंस्कृति ने 'वामपंथ' में मार्क्सवाद और साम्यवाद से लेकर लोकवाद तक तथा 'केन्द्र' में सौम्य सामाजिक लोकतंत्र से लेकर राजनीतिक विभाजन के 'दक्षिण पंथ' पर फासीवाद सहित कट्टरवादी और परा-रूढिवादी और प्राधिकारवादीप्रवृत्तियों और रूझानों की एक व्यापक

श्रृंखला उत्पन्न की है। इनमें से अधिकांश विचारधाराओं ने अनेक वर्षों से लातिन अमेरिका की निष्कर्ष और पवित्र व्यवस्थाओं जैसे क्यूबा तथा विभिन्न प्राधिकारवादी और फासीवाद प्रकृति के देशों जैसे ब्राजील और चिली का निर्माण किया है।

पश्चिमी विचारधारा में तथा नवीनतम संदर्श में लातिन अमेरिका का एक सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरुप उसकी सेना का है जिसे कथित रूप से 'मैन-ऑन-हॉर्सबैक' कहा जाता है और जो राजनीति में हस्तक्षेप करती है। अधिकांश क्षेत्रों में, स्वतंत्रता के उपरांत सेना ने समाज में एक प्रधान बल के रूप में सम्राट को सहायता प्रदान की है। आज भी, लोकतांत्रिक नियमों के प्रति लगभग तीन दशकों में होने वाले रूपांतरण तथा सत्तर और अस्सी के दशकों में अनेक सैन्य शासनों के उतार-चढ़ाव राजनीतिक क्षेत्र से दूर नहीं थे तथा अतीत से निर्णय लेने के लिए यह क्षेत्र किसी अन्य दिवस वापस सेना के शासन को वापस लाने से मुक्त नहीं है (होंडूरास में विद्रोह, जिसने 2009 में राष्ट्रपति जेलाया को अपदस्थ कर दिया था, को एक विपथन के रूप में माना जाता है तथापि, यह निष्कर्ष के तौर पर कह पाना जल्दबाजी होगी) साठ के दशक से पूर्व लातिन अमेरिका में सेना का भ्रमण तब हुआ था, जब उन्होंने उग्र रूप से सत्ता हासिल की थी, सुधार किए थे और सरकार के अवशेषों को जनता को वापस सौंप दिया था। साठ के दशक के बाद से अस्सी के दशक तक, सेना ने 'सामान्य-राजनीति के नारे को बदलने के तर्काधिकार के साथ विस्तारित अवधि के लिए शक्ति हासिल की। सेना के इस उद्देश्य को ' राजनीति-विरोध की राजनीति कहा गया है, जो अस्तित्वात्मक मुद्दों का समाधान करने के लिए तकनीकी आवश्यकताओं के प्रति अधीनस्थ राजनीति का प्रयास है जिसे प्रायः ' नौकरशाही प्राधिकार' के रूप में वर्णित किया जाता है। निष्कर्ष के तौर पर, यह विभिन्न राजनीतिक और प्रौद्योगिकियों के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए सेना, नौकरशाही और कुछ मामलों में व्यापारित समुदाय के बीच एक समझौता था जिसे सेना ने क्रियान्वित करना अनिवार्य समझा था। देश पर निर्भर करते हुए, इसमें स्पष्ट रूप से प्रेरित करने (सामन्यवाद के लिए स्वागतयोग्य कार्यवाही) से लेकर गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली स्पष्ट प्रवृत्ति तक हर बात शामिल है।

इसकी समस्त पूर्व और आगामी अभिव्यक्तियों में 'कॉडिलो' का प्राधिकारवाद और परंपरा, विखंडनशील राजनीतिक संस्कृति, प्रशासन को बहुलवाद और अनेक कट्टरवादी राजनीतिक विचारधाराओं के विरुद्ध खड़ा करने, तथा घरेलू क्षेत्र में एक एजेंसी के रूप में 'सेना' का व्यापक रूप से प्रयोग में लाने के फलस्वरूप अधिकांश लातिन

अमेरिकी देशों के राजनीतिक दृष्टि से अधिक उग्र बन गए जिससे राजनीतिक स्थायित्व प्रभावित होता है और उदारवादी लोकतंत्र की प्रगति यौगिक हो जाती है। उन्नीसवीं शताब्दी की समाप्ति से लेकर तीस के दशक तक उभरने वाले नवीन लोकतंत्र की अवधि के उपरांत प्राधिकारपूर्ण सेना शासन का एक लंबा चरण आया जब महामंदी के दौरान लातिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई थीं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से साठ के दशक तक लोकतांत्रिक विकास की द्वितीय लहर के बाद एक प्राधिकारपूर्ण और अत्यंत उग्र अवधि आई। अस्सी के दशक के प्रारंभ की अवधि तो तथाकथित 'लोकतंत्र की तीसरी लहर' उत्पन्न की। परंतु निर्णायक अभी भी इसका पता लगा रहे हैं कि क्या इसने लोकतांत्रिक नियम के अपरिवर्तनीय समेकन को गठित किया है अथवा यह केवल परा-महाद्वीप में राजनीतिक विकास के इस कोलर कोस्टर भ्रमण में केवल एक अन्य चरण था।

उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान, लातिन अमेरिका में प्राधिकारपूर्ण राजनीतिक संरचनाएं नेतृत्व की 'कॉडिलो' शैलियों के रूप में अभिव्यक्त की गई थीं। कार्यशील लोकतांत्रिक प्रणाली के अभाव में, जो एक नागरिक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में शांतिपूर्ण और बाधारहित शक्ति के हस्तांतरण को अनुमति देती है, महलों में विद्रोहों तथा सैन्य शासनों की एक बड़ी श्रृंखला को जन्म दिया है। स्वतंत्रता पर पितृसत्तात्मक प्रथाओं के समाप्त होने पर दृश्यमान शक्ति निर्वात के जूझते हुए उस समय के नेताओं ने संसक्त विचारधारा के प्रतिपादन और अभिव्यक्ति के माध्यम के स्थान पर चमात्कारी संपर्क के मिश्रण तथा पारपंरिक अपीलों के माध्यम से वैधता हासिल करने का प्रयास किया। 'कौडिलो', जो लातिन अमेरिका की एक विशिष्ट शैली है, मोटे तौर पर 'शक्तिशाली मॉडल की सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें राजनीतिक तत्वों को संगठित रखने के लिए और साथ ही केन्द्रीय नेता के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा को प्रोत्साहित करने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करने के स्थान पर अपने चमत्कार का प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। जो बात रुचिकर है, वह यह है कि ये 'कॉलिडो' विभिन्न स्वरूपों एवं तरीकों में आते हैं तथा विविधतापूर्ण विचारधाराओं में गुंथे होते हैं जिनके माध्यम से एक ओर 'रूढिवादी' अथवा' उदारवादी अभिमुखीकरणों के साथ वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी प्रतिबिंबित होती है तथा दूसरी ओर ये 'नागरिक' और 'सेना' शासन संबंधी अभिव्यक्तियों के बीच झूलती रहती हैं। इसके अलावा, ऐसे कॉडिलो की सुसभ्य अथवा ग्राम्य पृष्ठभूमियों से प्रशंसा भी प्राप्त करते हैं तथा इन्होंने या तो आधुनिक प्रवृत्ति प्रदर्शित की

है अथवा ये पारंपरिक रूढ़िवादी संदर्शों में गुंजायमान होते हैं।

बीसवीं शताब्दी के दूसरे भाग में, प्राधिकारपूर्ण सैन्य व्यवस्थाओं में वैयक्तिक तानाशाही का प्रवेश हो गया, विशेष रूप से ब्राजील और बोलीबिया (1964) अर्जेंटीना (1966), उरुग्वे और चिली (1973) के देशों में। ये प्राधिकारपूर्ण व्यवस्थाएं प्रपीड़क बल का निरकुशं तरीके से प्रयोग करते हुए और राजनीतिक विरोधियों को सलीके से समाप्त करते हुए आंतरिक असंतोष को निर्दयतापूर्ण कुचल देने की उनकी नीति में अद्वितीय थीं जैसा कि चिली में पिनोचेट की प्रणाली में दिखाई देता है तथा विडेला में अर्जेंटीना में अनेक कार्यकर्ताओं और विरोध प्रदर्शन करने वालों की रहस्यमयी गुमशुदगी में दिखाई देने वाली झलक के संदर्भ में नागरिक समाज और राजनीतिक आंदोलनों को कुचलने की प्रवृत्ति में दिखाई देता है जिन्हें ब्यूनस आयर्स में मदर्स ऑफ प्लाजा दी मायो द्वारा अभी भी स्मरण किया जाता है। वामपंथी धमकियों का उदय होने की आशंका में जो निर्वाचकों के गठबंधन अथवा सशस्त्र छापामार आंदोलनों, दोनों से उत्पन्न हो सकती थी, ये प्राधिकारपूर्ण शासक पारंपरिक प्रणालियों के आधार पर अपने देशों की संरचना को पुन: संरेखित कर दिया करते थे। किसी वैयक्तिक तानाशाह की व्यक्तिगत ताकत पर विश्वास करने के स्थान पर ये शासक समाज पर नियंत्रण करने के लिए शांति बहाल करने के प्रयोजनार्थ सैन्य संस्थाओं का निर्दयता के साथ प्रयोग किया करते थे।

परिणामी 'नौकरशाही प्राधिकारीपूर्ण' व्यवस्थाओं ने नव-उदारवाद प्रवृत्तियों के साथ उनके देशों को सुधारने के लिए आधारभूत रूप से राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं को पुन: आदेशित किया जिसने आयात प्रतिस्थानी औद्योगिकीकरण की संरचनाओं को तोड़ दिया तथा आंतरिक दृष्टि से ऋण-चालित विकास की रणनीतियों को प्रारंभ किया जिसकी परिणति अंतत: सामाजिक-आर्थिक विस्थापन के अलावा अमीरों और निर्धनों के मध्य अंतर को नाटकीय रूप से व्यापक बनाने के रूप में 1982 के लड़खड़ाते लातिन अमेरिकी ऋण संकट के रूप में हुई। ऐसे विषम आर्थिक सुधार इतने अलोकप्रिय थे कि उन्हें केवल गैर-लोकतांत्रिक तरीकों से अधिरोपित किया और कायम रखा जा सकता था। संरचनात्मक समायोजनों के प्रति लोकप्रिय प्रतिक्रियाओं, जिन्होंने रहन-सहन के मानकों को तेजी से कम किया, ने प्राधिकारपूर्ण शासनों का नेतृत्व उनके विरोधियों को और अधिक निर्ममता के साथ दमन करने की दिशा में किया।

अल्बर्टो फ्यूजीमोरी की की पेरू में 1990-2000 की व्यवस्था लातिन अमेरिका

में अधिकारपूर्ण परंपरा का एक अन्य प्रकार प्रस्तुत करती है। इसे 'आटोगोल्पे (स्व-विद्रोह) अथवा 'फ्यूजी-विद्रोह' के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत फ्यूजीमोरी ने अप्रैल, 1992 में कांग्रेस को समाप्त करने और एंडियन देश के संविधान को पुन: लिखने के लिए अप्रैल, 1992 में स्वयं के विरुद्ध ही विद्रोह प्रारंभ किया था। 'अर्ध-प्राधिकारवाद के मैशियावेलियन उपकरण का प्रयोग करते हुए फ्यूजीमोरी ने कुछ अर्थपूर्ण नीतिगत उपलब्धियां हासिल की थी जिनमें मंहगाई को कम करना और शाइनिंग पाथ छापामार उग्रवाद की सफलतापूर्वक समाप्ति करना, कानून-व्यवस्था को बहाल करना तथा समस्त पेरू पर राज्य का ऐसा प्राधिकार पुन: स्थापित करना शामिल था जिससे उसके द्वारा पेरू की संवैधानिक व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने के बावजूद उसकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई। इसके स्थान पर, अनेक प्रेक्षकों का मानना है कि देश के संकट ने सुदृढ़-सशस्त्र उपायों को वैध बनाया। तथापि, सहस्राब्दि की समाप्ति तक, यह संकट गुजर गया तथा उसके द्वारा शक्ति के सुस्पष्ट और दण्डमुक्ति की भावना से ग्रस्त दुरुपयोग के लिए जन भावना का समर्थन समाप्त हो गया। इस दिशा में, तत्पश्चात् उसे सत्ता से हटाए जाने को न तो लोकतंत्र की विजय के रूप में देखा जाता है और न ही प्राधिकारवाद को लगे एक धक्के के रूप में, बल्कि उसे एक गतिशील राजनीतिकस्थिति के प्रति लोकप्रिय प्रतिक्रियाओं के परिणाम के रूप में देखा जाता है।

बीसवीं शताब्दी की समाप्ति तक, समूचे लातिन अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकारों के पुन: उदय होने के साथ ही प्राधिकारवादअतीत में सुरक्षित रूप से लुप्त होता प्रतीत हुआ। फिर भी, हम लोकतांत्रिक संरचनाओं के प्रति 'दक्षिणपंथी' चुनौतियों में एक प्राधिकारपूर्ण परंपरा की विद्यमानता की ओर इशारा कर सकते हैं। ये 'अभद्र आंदोलन' जो बहिष्कारक उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राजनीतिक हिंसा का प्रयोग करते थे, आवश्यक तौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियों को समाप्त करने का आशय नहीं रखते थे, परंतु फिर भी, वे लोकतांत्रिक संस्थाओं के मार्ग और प्रक्रियाओं को दिशा देने में समर्थ थे। सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्राय: तलाश निरंतर एक भ्रामक लक्ष्य बनी रही। सूक्ष्म और कभी-कभी इतने सूक्ष्म नहीं, तरीकों से प्राधिकारवाद लातिन अमेरिका में अभी भी पहचानी जाने वाली ताकत बना हुआ है।

आर्थिक विकास रणनीतियां- लातिन अमेरिकी मंचों पर 'आईएसटी' एवं 'वाशिंगटन समझौता'

लातिन अमेरिका की स्वतंत्रता-उपरांत विकास रणनीतियों को तीन परस्पर आच्छादित चरणों में विभाजित किया जा सकता है; प्राथमिक उत्पाद विशेषीकरण की अवधि (महामंदी से पूर्व), आयात प्रतिस्थानी औद्योगिकीकरण(उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ हुआ परंतु 1930 और 1970 के बीच चरम पर आया) तथा मुक्त-बाजार आर्थिक सुधार (अस्सी के ऋण संकट के पश्चात् प्रधानता)।

उन्नीसवीं शताब्दी के बाद से महामंदी तक की अवधि में लातिन अमेरिका उस समय प्राथमिक उत्पादों के निर्यातक और विनिर्मित वस्तुओं के आयातक के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतर्वेशित रहा। उत्पादन और व्यापार का यह पैटर्न क्रमशः उपनिवेशी स्पेन और पुर्तगाल का पक्ष लेने वाले द्वारा अनेक वर्ष पूर्व अधिरोपित किया गया था, परंतु यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त की विद्यमान प्रणाली द्वारा डाले गए भार के फलस्वरूप आंशिक तौर पर क्षेत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। जैसे-जैसे उद्योग ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस से बाहर फैला, विनिर्माता अमेरिका और यूरोपीय विनिर्मित वस्तुओं को खरीदने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमुख बैंकों के साथ घनिष्ठता से स्वयं को संरेखित करने लगे जिन्होंने लातिन अमेरिका के नए स्वतंत्र हुए देशों को ऋण प्रदान किया। इसके अलावा, पश्चिम में औद्योगिकीकरणकी तेज गति ने तत्कालीन उपनिवेशों से कच्चे माल के लिए भारी मांग पैदा की जिनमें लातिन अमेरिका प्रमुख था। इस भारी मांग का लाभ उठाने के लिए, लातिन अमेरिका के राष्ट्रों ने भौतिक अवसंरचना के निर्माण के लिए भारी ऋण लिया, पत्तनों, रेलवे और सड़कों में भारी पूंजी निवेश किया जो ऐसे निर्यात-योग्य पण्यों की आवाजाही के लिए आवश्यक था। सिद्धांत रूप में, लातिन अमेरिका का बढ़ गया ऋण सृजित किए गए राजस्व से संवर्धित आउटपुट और प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात द्वारा चुका दिया जाना था। तथापि, व्यावहारिक रूप में, प्राथमिक निर्यातों पर ऐसी निर्भरता एक गंभीर आर्थिक अभिप्राय साबित हुआ।

प्राथमिक वस्तु उत्पादन में विशेषज्ञता और साथ ही विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित प्राथमिक उत्पादों के लिए व्यापार के गिरते निबंधनों ने लातिन अमेरिका लातिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं को बाजार में हुए उतार-चढ़ावों के प्रति गंभीर रूप से सुभेद्य बना दिया था। महामंदी के दौरान वस्तुओं के मूल्यों में हुई गिरावट के बाद, अनेक लातिन अमेरिकी देशों ने आर्थिक विकास के एक नए चरण का अनुपालन प्रारंभ कर दिया जिसे आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण (आईएसआई) कहा जाता है।

आईएसआई विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन के लिए लातिन अमेरिकी देशों द्वारा अपनाए गए आयात उपायों के रूप में प्रारंभ हुआ था जिन्हें पण्य बाजारों और मूल्यों में संकट के परिणामस्वरूपउनके स्टोरों के बाहर से अब अर्जित नहीं किया जा सकता है, जिसने उन्हें विनिर्मित वस्तुओं के संभावित आयातों को वित्त-पोषित करने के लिए नकद मुद्रा से वंचित कर दिया। हालांकि समय के साथ, आईएसआई एक आर्थिक रणनीति बन गया जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादित समतुल्य वस्तुओं के साथ आयातित विनिर्मित वस्तुओं के विनिर्माण को अनुपूरित करते हुए औद्योगिकीकरण का प्रारंभ करना था। आईएसआईटैरिफों और कोटों को अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप के माध्यम से लाया गया जिसे नवीन घरेलू उद्योगों को विदेश प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया था। एक लातिन अमेरिकी अभिनवता न रखते हुए, वस्तुतः सभी औद्योगीकृत देशों ने घरेलू औद्योगिक आधार के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आईएसआईअवयवोंका प्रयोग किया।

लातिन अमेरिका में, आईएसआईने औद्योगिक परिणामोंमें नाटकीय वृद्धि हासिल की। आर्थिक विकास के उच्च स्तर प्राप्त किए और अत्यंत गुणवत्तापूर्ण जीवन-यापन मानक हासिल किए, परंतु इन्होंने प्राथमिक उत्पाद निर्यातों में क्षेत्र की विशेषज्ञता में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया। चूंकि आईएसआई परिणामों और मशीनरी के आयात पर निर्भर था, लातिन अमेरिकी देशों ने आईएसआई उद्योगों को प्रचालन में रखने हेतु बहुमूल्य विदेश मुद्रा अर्जित करने के लिए खनिजों और कृषि पण्यों के निर्यात पर निर्भर रहना जारी रखा। साठ के दशक में शुरू करते हुए, कुछ लातिन अमेरिकी देशों (विशेषतः ब्राजील और मेक्सिको) ने निर्यातों को गहन करने तथा अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से निर्यातोन्मुखी उद्योग का विकास करने को प्राथमिकता प्रदान की। जबकि लातिन अमेरिकी विनिर्मित निर्यात में 1967 और 1980 के बीच पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, फिर भी, अधिकांश औद्योगिक उत्पादन घरेलू बाजार की ओर उन्मुख रहना जारी रहा तथा क्षेत्र की प्राथमिक पण्य निर्यात पर निर्भरता भी निर्बाध रूप से जारी रही।

दक्ष , आन्तरिक रूप से प्रतिस्पर्धी उद्योगों के पक्ष में अपनी उत्पादक संरचना को परिवर्तित करने की लातिन अमेरिका की विफलता का श्रेय उस बात को दिया जा सकता है, जिसे लोकप्रिय रूप से 'प्राकृतिक-संसाधन श्राप' के रूप में जाना जाता है। इसके अनुसार, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन रखने वाले देशों को अधिक जटिल आर्थिक

पुनर्संरचना संचालित करने के स्थान पर विकास दरों को बनाए रखने तथा भुगतान शेष संकट को टालने के लिए सामान्यतः प्राथमिक पण्य निर्यातों की प्रमात्रा में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वस्तुतः अन्य उद्योगों को प्रोत्साहित करने से प्रायः कृषि और खनिज समृद्ध-वर्ग की ओर से विरोध को बढ़ावा मिलता है, जो प्राथमिक उत्पाद उत्पादन से लाभान्वित होते हैं।

आईएसआई कार्यनीति की समाप्ति और पतन अस्सी के दशक में अत्यंत विषय ऋण संकट द्वारा प्रारंभ हुआ। सत्तर के दशक के प्रारंभ में, ओपीईसी द्वारा पेट्रोलियम मूल्यों में की गई उल्लेखनीय वृद्धि के प्रत्युत्तर में, अनेक विकासशील देशों ने पेट्रोलियम, मशीनरी तथा औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक अन्य उत्पादों का वित्त-पोषण करने के लिए प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लिया। वाणिज्यिक बैंकों ने ओपीईसी राष्ट्रों द्वारा उनके कोषों में जमा किए गए 'पेट्रो डॉलरों पर ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से इन देशों द्वारा व्यापक तौर पर उधार लेने की प्रक्रिया तेजी के साथ प्रोत्साहित किया। जब 1979-80में अतिरिक्त तेल मूल्यों ने ब्याज की दरों को ऊंचाई पर पहुंचा दिया, ठीक वैसे ही, जैसे प्राथमिक पण्यों के लिए विश्व बाजार मूल्यों में भारी गिरावट आई थी, लातिन अमेरिका के देशों सहित अनेक विकासशील देश अपने ऋण वापसी के दायित्वों की पूर्ति करने में असमर्थ थे। इस ऋण एवं कर ने लातिन अमेरिकी देशों को उनके पुनर्भुगतान को सुकर बनाने के लिए ऋणों की पुनर्संरचना करने के प्रयोजनार्थ आईएमएफऔर विश्व बैंक के साथ वार्तालाप के अनेक चक्र आयोजित करने के लिए विवश कर दिया। अस्सी के दशक के मध्य तक, लगभग, तीन-चौथाई लातिन अमेरिकी देश आईएमएफऔर विश्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित ऋण पुनर्भुगतान कार्यक्रमों के अंतर्गत संघर्ष कर रहे थे।

आईएमएफ और विश्व बैंक की सहायता की शर्त के रूप में, विकासशील देशों को संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों को अपनाना अपेक्षित है जिसमें नव-उदारवाद आर्थिक सुधारों की मानक प्रकृति शामिल हो, जिनका निर्माण अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और प्रचालन में सरकार की भूमिका को कम करने के लिए तथा निजी क्षेत्र में अधिक शक्ति और संसाधनों को समर्थ बनाने के लिए किया जाता है। वाशिंगटन समझौते के रूप में ज्ञात इन सुधारों में शामिल था - उद्योग और लोक सेवाओं का गैर-विनियमन और निजीकरण, व्यापार उदारवाद, सरकारी व्ययों की कटौती, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और वित्तीय उदारवाद की बाधाओं का उन्मूलन। वांशिगटन समझौते का बल निर्यात-

चालित विकास पर दिया गया था और विशेषीकरण का अनुमान प्रतिस्पर्धी लागत लाभ के आधार पर लगाया गया था तथा उसने नए, गतिशील आर्थिक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के स्थान पर प्राथमिक पण्यों के निर्यातपर लातिन अमेरिका की ऐतिहासिक निर्भरता को पुन:प्रवर्तित किया। लातिन अमेरिकी देश पारंपरिक प्राथमिक पण्यों (जैसे सोय और कॉपर), 'गैर-पारंपरिक' कृषि उत्पादों (जैसे स्ट्राबेरी और फूल) तथा निम्न प्रौद्योगिकी विनिर्मित माल (जैसे जूते और वस्त्र) के निर्यात को प्रोत्साहित कर रहे थे जिन्हें कम मजदूरी वाले एसेम्बली प्लांटों में तैयार किया जाता था जिन्हें माक्तवलाडोराकहा जाता था। इसके अलावा, लातिन अमेरिकी देशों से उनके बाजारों को सस्ते आयातित विनिर्मित माल के लिए खोलने की अपेक्षा करते हुए, वाशिगंटन समझौते ने स्थानीय फर्मों को दिवालिया कर दिया तथा क्षेत्र के औद्योगिक भविष्य को खतरे में डाल दिया।

वाशिगंटन समझौते की शर्तों के अनुपालन के फलस्वरूप साठ और सत्तर के दशक की तुलना में आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय मंदी आई, उधारी में वृद्धि हुई और सामाजिक और राजनीतिक असंतोष भी काफी बढ़ा। लातिन अमेरिकी देशों में समय-समय पर दंगे भी भड़का करते थे जिनमें काफी लोग मारे जाते थे और घायल होते थे तथा इनके परिणामस्वरूप लाखों डॉलर की लूटपाट हुई तथा जन संपत्ति को नुकसान पहुंचा। नब्बे के दशक के प्रारंभ में आरंभ हुए निचले स्तर वाले सामाजिक आंदोलनों ने जनता को एकजुट किया, हड़तालें और लोकप्रिय विद्रोह भी किए गए ताकि शासन प्रणालियां आईएमएफ, विश्व बैंक तथा प्रमुख परा-राष्ट्रिक निगमों के निकट आईं और इनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित किए गए।

नब्बे के दशक में, नव-उदारवाद लातिन अमेरिका में गहन पैठ बना चुका था और वह राजनीतिक परिदृश्य पर भी छा गया था। यह कार्यक्रम पिनोचेट के चिली में मूलत: कट्टर दक्षिणपंथियों द्वारा क्रियान्वित किया गया था, तथापि, इसने पेरू में एल्बर्टो फ्यूजीमोरी के रूप में अन्य दक्षिणपंथियों में भी अपनी पकड़ बना ली, यहां तक कि उन सम्मिलित बलों पर भी जो आर्थिक राष्ट्रवाद के साथ ऐतिहासिक रूप से सहयोजित थे : मेक्सिको में इंस्टिट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी (पीआरआई), कार्लोस मेनेम के अधीन अर्जेंटीना में पेरोनिज्म, बोलीविया में नेशनललिस्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, वह दल जिसने विक्टर पाज़ एस्टेंसोरो के अंतर्गत 1952 की राष्ट्रवादी क्रांति का अगुआई की थी। इसके होते हुए भी, नव उदारवाद सामाजिक लोकतंत्र की ओर बढ़ा तथा

उसने चिली की सोशलिस्ट पार्टी, वेनेजुएला की एकिनो डेमोक्राटिका और ब्राजील की सोशल-डेमोक्रेटिव पार्टी का समर्थन हासिल कर लिया था। यह लातिन अमेरिका के लगभग संपूर्ण भू-भाग पर शासक प्रणाली बन गई।

फिर भी, नव-उदारवाद मॉडल इसके सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक सामाजिक बल को समेकित कर पाने में विफल रहा, जिसके फलस्वरूप संकटों के उदय की जल्द ही समाप्ति हो गई जिसने इसके मार्ग को नियंत्रित कर लिया। तीन विशालतम लातिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाएं सर्वाधिक नाटकीय संकट के स्थल बन गई थीं : 1994 में मेक्सिको, 1999 में ब्राजील और 2002 में अर्जेंटीना, तथा यह कार्यक्रम अपनी संभावनाओं को क्रियान्वित किए बिना ही लड़खड़ा गया। यह ठीक है कि भारी महंगाई की क्षति को नियंत्रित कर लिया गया था परंतु इसे एक भारी कीमत पर हासिल किया गया था। एक दशक अथवा अधिक से आर्थिक विकास बाधित था, लोक-ऋण व्यापक थे तथा जनता के एक बड़े वर्ग ने अपने अधिकारों का शोषण होते हुए देखा, विशेष रूप से रोजगार और श्रम संबंधों के क्षेत्र में। इन सबसे ऊपर, राष्ट्रीय ऋण भी काफी बढ़ गए थे तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं अत्यंत सुभेद्य बन गई थीं और वे सट्टेबाजों के लिए खुल गई थी जैसाकि इन तीन देशों ने स्वयं ही अनुभव किया था।

यह लातिन अमेरिका में नव-उदारवाद का खराब आर्थिक निष्पादन ही था जिसने अधिकांश अवसरों पर उन सरकारों की पराजयों को जन्म दिया जिन्होंने उसे तैयार किया था। इनमें शामिल थे - पेरू में एल्बर्टो फ्यूजीमोरो, ब्राजील में फर्नांडो, अर्जेंटीना में कार्लोस मेनेम, वेनेजुएला में कार्लोस एंड्रीज़ पेरेज़ और बोलीविया में गेंजालो सांचेज डी लोजाडा। इसी आंधी में मेक्सिको में पीआरआई तथा उरुग्वे में दो पारंपरिक दलों का प्रत्यावर्तन भी बह गया था तथा इनमें वे राजनीतिज्ञ भी शामिल थे जिन्होंने नव उदारवाद को स्थायी बनाया था, यहां तक कि इसका पतन होने के बाद भी, जिसमें अर्जेंटीना में फेर्नांडो डी ला रुआ, एक्वाडोर में लुतियो गुटेरेज और बोलीविया में सांचेज डी लोजाडा भी शामिल थे।

समकालीन लातिन अमेरिका में 'वामपंथ' के रहस्य को खोलना

संपूर्ण लातिन अमेरिकी परिदृश्य में राष्ट्रपतीय चुनावों के घुमाव ने, जो 2005 के अंत से 2006 की समाप्ति के बीच घटित हुआ था, 'वामपंथ' के आरोहण के विचार को

प्रक्षेपित किया था, जो एक ऐसा विचार था, जिसने बाद में स्वयं को लोकप्रिय परिकल्पना और विद्वतापूर्ण मार्ग, दोनों ही में डाल दिया था। इसके बावजूद, वामपंथ के व्यापक उदय और पुन: उत्थान पर विशेष रूप से कोलम्बिया और मेक्सिको में क्रमिक निर्वाचन परिणामों द्वारा निरंतर आक्रमण किया जाता रहा तथा इसने यह दर्शाया कि 'वामपंथी' बलों के पुन: उदय की प्रक्रिया का दावा किसी भी प्रकार से परा-क्षेत्रीय अथवा सार्वभौमिक नहीं था। फिर भी, इक्कीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में शासन पर काबिज अनेक पदधारी राष्ट्रपतियों और नेताओं, जिन्होंने स्वयं को अपने अभिविन्यास में 'वामपंथी' वर्णित किया और/अथवा प्रबंधक दलों और राजनीतिक संगठनों ने 'वामपंथ' को ऐतिहासिक दृष्टि से परिकल्पित किया, चाहे वह चिलियन सोशलिस्ट हों, ब्राजील में पार्तिदो दो त्राबल हैडोरज़ (कामगारों की पार्टी) हो, अथवा इस मामले में, उरुग्वे में फ्रेंटे एम्प्लियो (ब्रॉड फ्रंट) हो, तथा इसने असंदिग्ध प्रवृत्ति को पुन: प्रवर्तित करने की दिशा में कार्य किया; जिसकी उत्पत्ति 1998 में वेनेजुएला में ह्यूगोचावेज के लोकप्रिय निर्वाचन में हुई थी तथा जिसने 2006की समाप्ति तक क्षेत्र की 570 मिलियन जनसंख्या में से 60 प्रतिशत जनसंख्या पर राजनीतिक परिदृश्य के 'वामपंथी' आयाम में लोकप्रिय रूप से निर्वाचित सरकारों के रूप में शासन किया। 2008 के मध्य में दक्षिण अमेरिका के मानचित्र पर एक सरसरी नज़र दौड़ाने से यह पता चलता है कि दक्षिण अमेरिका में इन दस व्यवस्थाओं में कम-से-कम आठ स्पष्टत: वामपंथी थीं तथा यदि हम निकारागुआ में राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा, हैती में रेने प्रेवल, डोमिनिका गणराज्य में लियोनेल फर्नाडीज़ और पनामा में मार्टिन टोरिजोस के शासन कालों को भी शामिल करते हैं, तो इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में 'वामपंथ' की समाप्ति अत्यंत स्पष्ट प्रतीत हो रही थी।

तथापि , यह घटनाक्रम ऐसे समय में पूर्ववर्ती वर्णनों के विरोधाभास में था जब अधिकांश क्षेत्र कट्टरवादी वृहद्-अर्थव्यवस्था और सांस्थानिक सुधारों को सतर्कतापूर्वक क्रियान्वित करने के प्रति राजनीतिक दृष्टि से दृढ़ संकल्प था जिसके साथ तथाकथित 'वाशिंगटन समझौता' ढांचा भी शामिल था। 'बाजार लोकतंत्र' उस समय विद्यमान एकमात्र प्रणाली थी जो प्रतिनिधिकारी लोकतंत्र, बाजार-हितैषी सुधारों के अधिनियमन तथा निरंतर वैश्वीकृत होते जा रहे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की प्रवृत्तियों और बलों के मुक्त अनुभव का सम्मिश्रण थी। बाजार लोकतंत्र की व्याख्या लोकतांत्रिक समेकन के सफल परिणाम के रूप में की गई थी जो शीत-युद्ध की अवधि की सैन्य व्यवस्थाओं से लेकर शीत-युद्ध के बाद के उदारवादी राज्यों तक संक्रमण काल के दौरान सुदृढ़ हुआ

था और जिसने अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और उरुग्वे तक पहुंच बनाई थी। अनेक आर्थिक उतार-चढ़ावों और सामाजिक असंतोष के बाद, अनेक सुधारवादी आधार वाले दलों को चुनावों में सफलता हासिल हुई, जिन्होंने नब्बे के दशक के विफल प्रतीत होने वाले सामाजिक-आर्थिक मॉडलों को क्रियान्वित किया तथा जिन्होंने इसके फलस्वरूप कोई लोकप्रिय श्रेय हासिल नहीं किया। तथापि, लातिन अमेरिका के बाजार लोकतंत्रों को समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगा। राष्ट्रवादी, राज्य-प्रायोजित विकास और सरकार द्वारा नियंत्रित बाजार विनियमन ने क्षेत्र में बाजार सुधार के पूर्ववर्ती स्वरूप को सहायता दी।

हाल के वर्षों में, चुनावपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए व्यवहार्य तर्काधार की हिमायत करने वाली एक प्रचालनात्मक अटकल क्षेत्र में नव-उदारवाद आर्थिक सुधारों के दो दशकों के व्यापक रूप से साझे सामाजिक लाभों का वितरण कर पाने में उसकी योग्यता तथा पारपंरिक राजनीतिक समृद्ध-वर्गों की नि:शक्तता के संदर्भ में हासिल की गई विफलता और साथ ही शासन तथा संबंधित प्रक्रियाओं और तंत्रों में अधिक पहुंच, समानता, प्रतिभागिता तथा सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक अंतर्वेशन के लिए मांग के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त करने में पारंपरिक समृद्ध-वर्गों की अक्षमता के साथ एक व्यापक लोकप्रिय असंतोष और खिन्नता की ओर इशारा करती है। इस बात में अधिक विवाद नहीं है कि हाल के वर्षों में हासिल की गई आशाजनक आर्थिक वृद्धि के बावजूद गरीबी उन्मूलन एक मुख्य चुनौती बना हुआ है (लगभग 40 प्रतिशत लातिन अमेरिकी अभी भी 2 यूएस डॉलर प्रतिदिन पर निर्वाह करते हैं) तथा लातिन अमेरिका की गणना अभी भी विश्व में सर्वाधिक असमान आय वाले समाजों में की जाती है जो विकास की दिशा में संरचनात्मक समायोजन नीतियों की विफलता का एक परिकल्पित वर्णन है। किसी मामले में, हम वामपंथ के उदय और उसकी सदृढ़ता का श्रेय लोकतंत्र की गुणवत्ता और अनुकरण के साथ लोकप्रिय अनाकर्षण और विभ्रांति, निरंतर विद्यमान गरीबी और असमानता, लोकतांत्रिक सरकारों के प्रति भ्रांति, प्रतिभागिता और उत्तरदायित्व को देते हैं तथा साथ ही वैश्वीकरण की ज्यादतियों के कारण घरेलू और विदेश नीति के प्रतिकूल प्रभावों के चलते यह एक लोकप्रिय धारणा बन गई कि 'वामपंथ' को एक प्रकार के तनाव मुक्त करने वाले शासन और अमृत के रूप में माना जाने लगा। यह 1998 में वेनेजुएला में ह्योगो चावेज के निर्वाचन का वर्णन करता है जिसने क्रमश: 2006 और 2012 में

क्रमिक विजय हासिल की थी; चिली की समाजवादी पार्टी के लिए चुनावपूर्व राजनीतिक गतिविधियों की सफलता, जिसका 1999 में रिकार्डो लागोस द्वारा और बाद में 2006 में माइकल बैशलेट द्वारा नेतृत्व किया गया था, 2002 और 2006 में ब्राजील में लुइस इनासियो लुका डा सिल्वा (लुका) की शानदार जीत (शानदार 80 प्रतिशत निर्वाचन अधिदेश के साथ) जिसके पश्चात् 2010 में समान श्रमजीवी पार्टी के दिल्मा रोस द्वारा शासन किया गया था। अर्जेंटीना में, प्रमुख वित्तीय संकट के दौरान, जिसने मुद्रा में भारी गिरावट कर दी थी तथा अर्थव्यवस्था और राजनीति में पर्याप्त उथल-पुथल किया था, पेरोनिस्ट पार्टी के नेस्टर किर्चनेर 2003 में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और उनकी नीतियां इतनी लोकप्रिय हुई कि उनकी पत्नी क्रिस्टीन फर्नांडीज 2007 में आसानी के साथ निर्वाचित हुई और पुन: 2011 में विजयी रहीं। उरुग्वे में ताबके वेजक्वेज अनेक वर्तमान नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों को समाप्त करने के वायदे पर 2004 में निर्वाचित हुए। हालिया सफल प्रशासनों में बोलीविया में दवो मोरालेस (2006 से), इक्वाडोर में राफेल कोरिया (2006 से) और लगभग एक दशक तक सत्ता से बाहर रहने पर 2007 में निर्वाचित निकारागुआ के डेनियल आर्टेगा शामिल हैं।

एकल अथवा अखंड सत्ता के रूप में लातिन अमेरिका में वामपंथ की विद्यमानता पर फौरन विचार किए जाने के बावजूद, अथवा इसी संदर्भ में अतीत में देखना क्षेत्र में 'वामपंथी' अभिव्यक्ति की विविधता के प्रति अन्याय करना होगा। सामाजिक-आर्थिक और सांस्थानिक सुधारों के साझे लक्ष्यों के बावजूद नीतिगत उपकरणों और रणनीतियों, जिनमें 'वामपंथी' सरकारों की सुदृढ़ता विद्यमान है, ने अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करने के उद्देश्य से जो कार्रवाही की है, वह अत्यंत ठोस है। उदाहरण के लिए, वेनेजुएला के चावेज प्रशासन तथा चिली के बैशलेट को साथ मिलाने के लिए किस बात ने प्रोत्साहित किया था? वेनेजुएला सरकार प्राय: राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक प्रणाली, दोनों ही के कट्टर रूपांतरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्राय: दावा करती है, जो पूंजीवाद से परे और एक स्थिर-समाजवादी मॉडल की ओर जाता है जिसे '21वीं शताब्दी का समाजवाद' कहा गया है। इस दौरान, चिली की सरकार ने बैशलेट के अधीन नब्बे के दशक में अपने लोकतांत्रिक पूर्ववर्तियों से विरासत में ली गई राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। इन उदाहरणों के परे तथा समूचे लातिन अमेरिका में, सरकार की पद्धतियों में विभेद भी स्पष्ट हैं। अर्जेंटीना में किर्चनेर प्रशासन की

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विदेश उधारदाताओं के साथ पूर्व की अनबन और साथ ही अर्जेंटीना के सापेक्षी सौम्य सामाजिक सुधारों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में अमेरिका के साथ पूर्व राजनीतिक विभेदों के कारण वामपंथी विचारधारा के रूप में परिकल्पना की जाती है। इसी कारण से लुला दा सिल्वा की ब्राजीली सरकार को कभी-कभी 'वामपंथी' कहा जाता है क्योंकि इसकी रूढिवादी बृहद आर्थिक नीतियों से निरंतर संबद्धता के होते हुए भी उसके अधिकांश नेताओं की सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा थी और शासक श्रमजीवी दल की कतिपय सैद्धांतिक विशेषताएं थी। राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा (ब्राजील), मिशेर बैशेट (चिली), तबारे वाजक्वेज (उरुग्वे) और निकारागुआ के डेनियल ओरटेगा समेकित सांस्थानिक ढांचे के भीतर निर्वाचन प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप सत्ता में आए। इसके विपरीत, राष्ट्रपति श्री और श्रीमती किर्चनेर, इवो मोरोलेस, राफेल कोरिया और ह्यूगो चावेज ने गहन, सतत् सामाजिक और सांस्थानिक संकटों का सामना करते हुए अपने देशों में सत्ता संभाली जिसने कुछ मामलों में पूर्ववर्ती निर्वाचित प्राधिकारियों द्वारा त्याग-पत्र दिए जाने को भी विवश किया। देशों के पहले सेट में, नव-उदार सुधारों ने पदधारी प्रशासकों की सत्ता पर काबिज होने की योग्यता को नवीकृत कर दिया। पूर्व में, कट्टरवादी बाजार सुधार चिली में पिनोचेट तानाशाही द्वारा क्रियान्वित किए गए थे, और उरुग्वे में उन्हें पारंपरिक द्विपक्षीय प्रणाली द्वारा प्रवर्तित किया गया है जिसे अंततः वाजक्वेज की फ्रेंटे एम्प्लियो पार्टी द्वारा चुनावों में हरा दिया गया था; ब्राजील और निकारागुआ में बाजार सुधार साठ के दशक के पूर्ववर्ती प्रशासकों द्वारा क्रियान्वित किया गया था।

संसूचित विश्लेषण, इस गतिकी को प्रश्न करने के प्रयास कि वामपंथी व्यवस्थाएं क्यों पुनः काबिज हुईं और इस बात की प्रक्रिया कि किस प्रकार ऐसी प्रणालियां पुनः स्थापित हुईं तथा साथ ही उन्हें आधार प्रदान करने वाले सामाजिक गठबंधनों के अर्थ को समझने का आशय रखना और ऐसे नेताओं द्वारा प्रतिपादित और अंगीकृत नीतियों के प्रकार ने एक ओर 'सैद्धांतिक वामपंथ' के मध्य विशेषताओं का पता लगाने का प्रयास किया जो 'सोशल डेमोक्रेट्स' में समाहित था जैसे चिली में रिकार्डो लागोस और मिशेल बाशेलेट, ब्राजील में लुला दा सिल्वा और उरुग्वे में तबारे वेस्क्वेज़, जिन सभी ने अपने-अपने देशों के राजनीतिक परिवेश में राजनीतिक दल/कार्यकारी गठबंधन स्थापित करने से शुरुआत की थी तथा जिनकी राजनीतिक विद्यमानता नब्बे के दशक के विवादास्पद नव-उदारवादी संरचनात्मक समायोजन आर्थिक मॉडल के

अधिरोपण को पूर्वदिनांकित करती थी। इसमें कतिपय लोकप्रिय राजनीतिक हस्तियां भी शामिल थी जो श्रमजीवी आधारित राजनीतिक संगठन का पक्ष लेती थीं, जो वामपथी - विचारधारा का प्रभाव छोड़ती थीं और पारंपरिक लातिन अमेरिकी लोकप्रियतावाद की बात करती थी और उस पर विश्वास रखती थी जैसा कि अर्जेंटीना में नेस्टर किर्चनेर की पेरोनिस्ट पार्टी अथवा पेरू में एलन गार्सिया की एलियांज पॉपुलर रेवोलुशिनेरिया अमेरिकाना (एपीआरए) में दिखाई देता है। इसके बिल्कुल विपरीत ख्यात 'लोकप्रिय वामपंथ' है जो ऐसे नए उभरते हुए लोकप्रिय नेताओं को शामिल करता है जो अपने करिश्माई नेतृत्व से सुदृढ़ राजनीतिक समर्थन को संघटित कर पाने में समर्थ रहते हैं जैसा वेनेज़ुएला में ह्यूगो बावेज (1998 से) तथा एक्वाडोर में राफेल कोरिया (2006 से) के मामले में देखा गया है। इसके एक अन्य प्रकार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जिसे 'वामपंथी आंदोलन' के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसका अनुसरण बोलिविया में इवो मोरोलेस द्वारा किया गया था, जिसने अन्य लोकप्रिय सामाजिक आंदोलनों से निकलते हुए सफलता हासिल की थी। एक अन्य लाभकारी परिभाषा, जो पूर्ववर्त के सत्व को समाहित करती है, इन विविधताओं को उनके संदर्भ में पास-पास रखना है जो ऐसे तत्वों के विरुद्ध बाजारोन्मुख नीतियों के साथ सामाजिक पुन:वितरित लक्ष्यों को संयोजित करते हैं जो राज्य नियंत्रण और आर्थिक राष्ट्रवाद के नैसर्गिक स्वरूपों की स्वत: ही हिमायत करते हैं।

इन 'नवीन वामपंथी' प्रशासनों को जोड़ने वाली सामान्य विशेषता उनका लोकतांत्रिक जन्म है; वे भी सत्ता में सैन्य शक्ति के स्थान पर प्रतिस्पर्धी निर्वाचन प्रक्रियाओं से आए हैं। सशस्त्र संघर्ष अतीत का एक हिस्सा बनता प्रतीत होता है जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रभावी राजनीतिक लोकतंत्र के अलावा हिंसक राजनीतिक परिवर्तन का कोई अन्य बेहतर विकल्प नहीं है। अपने अधिक रूढिवादी समकक्षों की भांति, ये वामपंथी प्रशासन इस प्रतिनिधिकारी लोकतंत्र के समेकन को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए एक प्रणाली के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर भी उन्होंने प्रणाली को एक कृत्रिम संलग्नक से स्वतंत्र करते हुए विशिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण तक पहुंचाया है जैसे 'बाजार लोकतंत्र'। आर्थिक सुधार एजेंडा जिसने इन सरकारों को चुनावों में विजयी होने में समर्थ बनाया है, के क्रियान्वयन ने आर्थिक समृद्ध वर्ग और साथ ही मध्यम वर्ग के वृत्तिकों के साथ विरोधाभास में वृद्धि की है जो प्राय: कतिपय सरकारी संस्थाओं और वृत्तिक निकायों में बेहतर स्थिति में आसीन होते हैं। मोरालेज़ प्रशासन अनेक क्षेत्रीय

सरकारों और कई विदेशी स्वामित्व वाली तेल कंपनियों, जिनमें ब्राजील सरकार के स्वामित्व वाली तेल कंपनी पेट्रो ब्रास भी शामिल है, संवैधानिक और सर्वोच्च न्यायालयों, दोनों के साथ विवादों में घिरा था। इसी प्रकार, चावेज ने पीडीईवीएसएकी नौकरशाही तथा समृद्ध वर्ग के स्वामित्व वाले मीडिया के साथ सदैव ही संघर्ष जारी रखा (अप्रैल, 2002 में चावेज सरकार के विरुद्ध विफल हिंसक विद्रोह के बारे में माना गया था कि उसे शक्तिशाली वेनेजुएलाई आर्थिक रूप से समृद्ध-वर्ग की मिलीभगत से संचालित किया गया था, जिसमें कथित रूप से कुछ विदेशी सरकारों द्वारा भी सहयोग किया गया था), किर्चनेट प्रशासन ने न्यायपालिका के कुछ वर्गों तथा कैथोलिक गिरिजाघर के नेतृत्व के साथ संघर्ष किया था, तथा एक्वाडोर के राफेल कोरिया और एक्वाडोर संसद एवं न्यायालयों के बीच कड़ुए संबंध भी कुछ उल्लेखनीय मामले हैं।

लातिनक अमेरिकी सुधारवादी सरकारों की वर्तमान खेप को विविधतापूर्ण व्याख्याओं के अध्यधीन रखा जा सकता है। एक स्तर पर, इसे बीसवीं शताब्दी के लोकप्रिय शासनों के अप्रचलित पुनर्निर्माण के रूप में समझा जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों से राष्ट्रवादी रोधन के साथ आर्थिक कार्यों के अपारंपरिक प्रबंधन राज्य हस्तक्षेप के अति-विस्तार के फलस्वरूप अपने समाजों के लिए कभी-न-कभी नवीनतम प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला होता है। जन नायकवाद, अधिनायकवाद, लोकतांत्रिक संस्थाओं में छलसाधन तथा सामाजिक विरोधाभासोंकी हास्यास्पद रूप से उत्तेजना 'नवीन वामपंथ' के एक स्पष्ट प्राधिकारपूर्ण पक्ष की ओर इशारा करती है। सर्वाधिक उग्र संस्करणों में, यह व्याख्या इन प्रणालियों में से कुछ को अल्प परिमाण में चित्रित करती है जैसे ह्यूगो चावेज और इवो मोरालेज। एक वैकल्पिक संदर्श, लातिन अमेरिका में 'नवीन वामपंथ' को एक संक्रमणकालीन यात्रा के रूप में देखता है जो प्रारंभिक अवस्था में है और जो आर्थिक और सांस्थानिक, दोनों ही स्तरों पर अनिवार्य रूप से अधिक औचित्यपूर्ण निष्पादन प्रदान करता है। इस दौरान, कठोर आडम्बरपूर्ण, राष्ट्रवादी अथवा समाजवादी भाषा तथा निर्धनों के प्रति अत्यधिक उदार सामाजिक नीतियों का नवउदारवादी सुधारों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित निर्धनों और अन्य सामाजिक धड़ों के गुस्से अथवा असंतोष को कम करने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा, कतिपय अपरिहार्य आशोधनों के होते हुए भी, ये नीतियां वाशिंगटन समझौते के क्रियान्वयन द्वारा निर्धारित अनिवार्य विशेषताओं को बनाए रखती हैं। तबारे वाजक्वेज, लालू दा सिल्वा, नेस्टर और क्रिस्टीना फर्नानेंडेज-

किर्चनेर और सर्वाधिक ऊपर मिशेल बाशेलेट द्वारा प्रशासित किए गए प्रशासन इस संशयवादी विशेषता में सही बैठते हैं।

उनके विभेदों के बावजूद, दोनों दृष्टिकोण एक व्यापक सैद्धांतिक स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे वस्तुपरक कार्यों और तथ्यों के स्थान पर आडम्बर पर अधिक विश्वास करते हैं। अधिक विनिर्दिष्ट रूप में, वे ऐतिहासिक अभिलेखों पर, लोगों की स्मृतियों पर पुराने राजनीतिक अनुभवों पर और निरंतर की जा रही एवं पूरी न की गई अपेक्षाओं और मांगों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अंततः नवीन वामपंथ' वाली सुधारवादी सरकारें तथा उनके समक्ष आने वाले विवाद उनके देशों में नाटकीय रूप से राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरण की स्थिर प्रारंभिक प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। बोलीविया का मामला अत्यंत निदर्शनात्मक है, इसके अधिक विकसित क्षेत्रों की स्वायत्तता अथवा अलगाववाद के लिए पहलकदम, जहां 'भारतीय' पदाधिकारी हैं, दीर्घकालिक प्रादेशिक तथा नृजातीय-भाषायी ऐतिहासिक और वर्ग संबंधी विवाद झेलते हैं। अतः इवो मोरालेस सरकार ने न केवल राज्य-सुधार संबंधी बल्कि राज्य-निर्माण संबंधी चुनौतियों का भी सामना किया। किसी हद तक, यही एक्वाडोर का मामला भी है। ठोस, दीर्घकालिक राष्ट्रीय एकीकरण वाले समाजों में (जैसे चिली, ब्राजील, उरुग्वे अथवा अर्जेंटीना) राजनीति गहन सामाजिक असमानताओं द्वारा पोषित होती है और यह नव उदारवाद सुधारों के वर्षों के दौरान संवर्धित हुई। चिली के श्रमिकों और मध्य वर्ग के छात्रों की सड़कों पर आयोजित हिंसक रैलियां शिक्षा में भेदभाव, आधारभूत सेवाओं तक पहुंच और श्रमिकों की शर्तों में सुधार करने के बैशलेट प्रशासन के ढीले और उदासीन दृष्टिकोण के कारण बढ़ते हुए असंतोष की साक्षी हैं।

यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या 'वामपंथ' की ओर रूपांतरण स्थायी होगा। जबकि समकालीन वामपंथ के व्यापक सांतत्यक को वर्गीकृत करने के लिए प्रवणता का विरोध करने के लिए मामला बनाया गया है, जिसमें चिली के 'कंसर्टेक्शन' से अर्जेंटीना में 'किर्चेर्निज्म' शामिल है, यह आवश्यक बनाता है कि लोकतांत्रिक सरकारों की प्रथम लहर से इस 'वामपंथ' लोकतांत्रिक मोड से उल्लेखनीय वापसी, जिसने अस्सी के दशक में क्षेत्र के प्रगामी संक्रमण से लोकतंत्र की ओर प्रस्थान के उपरांत उन्हें सत्ता में काबिज कराया, की इसके उस गुण के कारण सम्यक रूप से सराहना की जाती है कि यह किसी विचारधारा तक सीमित नहीं रहता है। तत्कालीन 'वामपंथ' के कुछ पहलुओं पर पर्याप्त विचार किया गया है तथा एक भिन्न 'वामपंथ' उभरकर सामने आया है। देश किस बात

पर विचार कर रहे हैं, वह तार्किक रूप से लातिन अमेरिका राजनीति का कहीं गहन और सख्त रूपांतरण है ऐसा जो 'दक्षिणपंथ' और 'वामपंथ' के बीच शक्ति के संदर्भ में उत्साहहीन परिवर्तन से कहीं आगे जाता है, और जो उस तरीके को प्रभावित करता है जिसमें राजनीति क्रियान्वित की जाती है। जैसा कि पूर्व ब्राजीली समाजविज्ञानी आक्टोवियो इयानी ने कहा था, "लातिन अमेरिकी समृद्ध-वर्ग शासकों के रूप में नहीं, बल्कि स्वामियों के रूप में व्यवहार करते हैं।" इस प्रकार, लातिन अमेरिका के सुधारवादी लोकतंत्र अधिकांश शासनों के विरुद्ध एलेक्सिस डी टोक्विले की चेतावनी के बीच फंसकर रह गए तथा वे अल्पसंख्यकों के ऊपर शासन तथा घरेलू संपन्न-वर्ग के हठीपन और राजतंत्र का गढ़ बन गए।

लातिन अमेरिका में 'चीन' - इसकी समर्ग अर्थव्यवस्था का आधार

पिछले दशक में, चीन जनवादी गणतंत्र लातिन अमेरिका के लिए निरंतर एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार बन गया है, जिसने समूचे क्षेत्र में बीजिंग के निरंतर विस्तारित होते कदमों को देखा है। तथापि, इस अचूक प्रवृत्ति को अर्हक बनना चाहिए तथा इसे समुचित संदर्श में रखा जाना चाहिए। हालांकि चीन और लातिन अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध स्थिर रहे हैं और यह दोनों क्षेत्रों के लिए नए आर्थिक विकास का स्रोत भी है, यह एक अत्यंत छोटे आधार से उत्पन्न होता है तथा यह लातिन अमेरिका के पारंपरिक भागीदारों अर्थात् यूनाइटेड स्टेट्स और पश्चिमी यूरोप को विस्थापित करने अथवा अनुपूरित करने के आस-पास भी नहीं है, जो एक निश्चित काल के लिए लातिन अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों का प्रोफाइल और दर्जा धारण करना जारी रखेंगे। इसके अलावा, बीजिंग तथा लातिन अमेरिका की राजधानियों के बीच बढ़ती हुई पारस्परिक साझेदारी विस्तारवादी वैश्विक भू-राजनीतिक और रणनीतिक कारकों से पोषित हुई थी क्योंकि वे केवल पारस्परिक संभावनाओं और अवसरों पर आधारित है तथा द्विपक्षीय संबंध द्वारा इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। चीन इतिहास में सर्वाधिक उल्लेखनीय रूपांतरणों में से होकर गुजरा है। जबकि लातिन अमेरिका अस्सी के दशक के ऋण संकट और वाशिगटन समझौते की नीतियों के विस्थापक प्रभावों द्वारा काफी स्थिर हो गया था, चीन ने तीन दशकों की वृहद आर्थिक विकास लहर दर्शाई और 8-10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जिससे यह विश्व की दूसरी विशालतम अर्थव्यवस्था के रूप में उभर गया तथा विश्व का दूसरा विशालतम

निर्यातक हो गया जिसने अपने लगभग 400 मिलियन नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला तथा अभूतपूर्व ढंग से अवसंरचना का विकास किया। तथापि, बीजिंग का उदय और उसका आरोह केवल एक ऐसे विश्व की ओर वृहद् रूपांतरण का एक भाग ही है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का केन्द्र पूर्व से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गया क्योंकि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने निरंतर वृहद आर्थिक नियंत्रण अर्जित कर लिया था। लातिन अमेरिकी देश, अपने रणनीतिक प्राकृतिक संसाधनों (तेल, खनिज और धातुएं) के प्रचुर भंडारों तथा गरीबी (अभी भी 40 प्रतिशत लोग प्रतिदिन 2 यूएस डॉलर से कम पर जीवन-बसर करते हैं), बेरोजगारी, रुद्ध अवसंरचना आदि की संरचनात्मक समस्याओं से ग्रसित होने के साथ एक ऐसे समय में पीसीआर में एक व्यवहार्य साझेदार पाते हैं जब क्षेत्र में व्यवस्थाएं विकास के लिए वाशिगंटन समझौता ढांचे की नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों के व्यवहार्य विकल्पों की जोर-शोर से तलाश कर रही हैं। लातिन अमेरिका में नीति-निर्माताओं के लिए वर्तमान आर्थिक पैटर्नों तथा दीर्घकालिक वैश्विक प्रवृत्तियों दोनों के संदर्भ के भीतर चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखने की आवश्यकताहोगी।

पिछले एक दशक अथवा अधिक समय से चीन और लातिन अमेरिका के बीच पारस्परिक व्यापार अत्यंत तेजी के साथ बढ़ा है जिसमें लगभग पूरी तरह से चीन की रणनीतिक प्राकृतिक संसाधनों के नए स्रोतों के लिए भारी मांग का श्रेय है जो लातिन अमेरिका में प्रचुर मात्रा में हैं, चाहे वह तेल हो, खनिज-पदार्थ अथवा ईंधन हो, जिससे वह अपनी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति कर सकेगा। इसके अलावा, आकर्षक और तुलनात्मक रूप से उपयोग न किए गए लगभग 600 मिलियन लोगों के बाजार के बए चीन की कंपनियां और ब्रांड अपने उत्पाद प्रस्तुत करेगी। 2000 ओर 2010 के बीच पारस्परिक व्यापार में 1200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जो इस प्रकार की त्वरित वृद्धि थी जिसने बीजिंग को ब्राजील, चिली और पेरू के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य बना दिया तथा अर्जेंटीना, कोस्टा रिका और क्यूबा को दूसरे स्थान पर आकर्षक गंतव्य बना दिया जिसने पूरब के देशों को द्वितीय स्थान पर आने वाले देशों जैसे ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना और वेनेजुएला में सिद्धांत निर्दिष्ट करने के लिए विवश कर दिया क्योंकि इस बातचीत में इसके रणनीतिक भागीदार क्षेत्र के तीसरे विशालतम रणनीतिक भागीदारों के रूप में उभर रहे थे। फिर भी, पारस्परिक वाणिज्यिक अदला-बदली अभी भी कम बनी रही जो अमेरिका की लगभग एक-तिहाई थी तथा वह क्षेत्र के भीतर संसाधन बहुल देशों और क्षेत्रों में पूर्णत: संकेन्द्रित थी। चीन के लिए क्षेत्र के 83

प्रतिशत निर्यात के तथ्य में खनिज, धातुएं और कृषीय वस्तुएं (तांबा, लौह-अयस्क, तेल और सोयाबीन) थीं जैसा कि न्यून 5 प्रतिशत औद्योगिक और विनिर्मित माल की तुलना में उसके निकट रहना विचारणीय मामला बनता है। इसके अलावा, बीजिंग के लिए लातिन अमेरिका से लगभग 90 प्रतिशत निर्यात केवल चार देशों अर्थात् ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और पेरू से ही उत्पन्न होता था।

हालांकि , वस्तुओं के लिए चीन की मांग ने लातिन अमेरिका में आर्थिक विकास में तेजी ला दी थी, वस्तुओं के मूल्यों में नैसर्गिक अस्थिरता तथा निम्न मूल्य को शामिल करने वाले तथा कम श्रम वाले निर्यातों पर निर्भरता के कारण चीन पर प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात की अति-निर्भरता के संबंध में क्षेत्र की स्थिति के बारे में भय और चिंताएं व्यक्त की गई थी। उदाहरण के लिए, चीन के लिए चिली के कुल निर्यात का 81 प्रतिशत भाग तांबे और तांबा-अयस्क से मिलकर बना था, जोकि ऐसा उत्पाद था जो अप्रत्याशित मूल्य के अधीन था और वांछित अतिरेक नहीं था, यही स्थिति अर्जेंटीना के सोयाबीन उद्योग के लिए भी सही नहीं है, जिसमें दक्षिण अमेरिकी देशों के निर्यात का 74 प्रतिशत था, जो केवल चीन के लिए ही था। माल की कीमतों में परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए चिली और अन्य संसाधन बहुल देशों ने ऐसे निर्यातों से उद्भूत होने वाले लाभों को शिक्षा और रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण जैसे कल्याणकारी पहलों के प्रति लगा दिया।

इसके होते हुए भी, चीन और लातिन अमेरिका, दोनों देशों ने एक-दसरे के बाजारों में एक-दूसरे के लिए बाजार तक पहुंच बनाने के प्रयोजनार्थ कदम उठाए हैं। चिली 2006 में बीजिंग के साथ मुक्त व्यापार करार हस्ताक्षरित करने वाला पहला लातिन अमेरिकी देश था तथा पेरू और कोस्टारिका ने क्रमश: 2010 और 2011 में इस करार पर हस्ताक्षर किए। यह सुझाव देने के लिए एक बेहतर साम्राज्यिक साक्ष्य विद्यमान है कि द्विपक्षीय व्यापार में इन समर्थकारी ढांचागत समझौतों को स्थापित करने के उपरांत पर्याप्त वृद्धि हो गई है। उपभोक्ता उपकरणों, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल उद्योगों में चीनी ब्रांड अपनी कम लागत के कारण लातिन अमेरिका बाजारों में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने में सफल रहे हैं। तथापि, चीनी व्यापार प्रक्रियाओं तथा लातिन अमेरिकी देशों में स्थानीय उद्योगों और घरेलू क्षेत्रों पर उनके हानिकारक परिणामों के बारे में चिंताएं निरंतर उठती रही थीं, विशेष रूप से वस्त्र और परिधान क्षेत्र में जहां चीनी माल के

अम्बार को मेक्सिको जैसे देशों में स्थानीय उत्पादकों को बर्बाद करने के रूप में रेखा जा रहा था।

सुदृढ़ सतत् चीनी आर्थिक विकास ने उसे विश्व के शीर्ष पांच निवेशक देशों में स्थान दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र लातिन अमेरिका आर्थिक आयोग (ईसीएलएसी) के अनुसार, लातिन अमेरिका में चीन का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2010 में 15.3 बिलियन यूएस डॉलर था तथा 2011 में यह 22.7 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया जो पिछले नौ वर्षों में कहीं कम स्तर पर था। फिर भी, बीजिंग क्षेत्र में अमेरिका ओर नीदरलैंड्स के बाद तीसरा विशालतम बाहरी निवेशक बना हुआ तथा इसके निवेश का भाग अंतरक्षेत्रीय योग से कम है। हालांकि, तुलनात्मक दृष्टि से एक छोटे केन्द्र से प्रचालन करते हुए लातिन अमेरिका में चीनी निवेश में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसने 2010 में 15.3 बिलियन यूएस डॉलर और 2011 में 22.7 बिलियन यूएस डॉलर का आंकड़ा छू लिया, हालांकि पुन: वे अमेरिका को पीछे धकेलने के कहीं भी करीब नहीं थे, जो लातिन अमेरिका में धन-प्रेषण का एक प्रमुख स्रोत था, जिससे क्षेत्र ने 2010 में 60 बिलियन यूएस डॉलर में से 25 प्रतिशत भाग अर्जित किया था और उसके साथ वह क्षेत्र में अनेक देशों के लिए विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत भी है।

लातिन अमेरिका में चीनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), जो अमेरिका और नीदरलैंड्स के बाद तीसरे स्थान पर है, तीन मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है - संसाधन अर्जन, बाजार पहुंच और दक्षता प्राप्त करना। तथापि, यहां भी, निवेश का वैविध्यीकरण भ्रामक ही रहा है, जैसा कि ईसीएलएसी आंकड़े दर्शाते हैं कि बीजिंग की मुद्रा के निवेश का 90 प्रतिशत भाग संसाधन निष्कर्षित उद्योगों और सहयोजित क्षेत्रों में लगा हुआ है। 2010 में ही, बीजिंग ने वेनेजुएला, एक्वाडोर और अर्जेंटीना में तेल और गैस सौदों के अनुसरण में 13 बिलियन डॉलर से अधिक निवेश किया। इसके अलावा, अनेक चीनी कंपनियां, जो क्षेत्र में रणनीतिक संविदाओं के लिए बोलियां लगा रही थी, चीनी बैंकों से वित्त-पोषण जुटाने की उनकी योग्यता के कारण ऐसी संविदाएं हासिल करने में सफल रही हैं। उदाहरण के लिए, चीनी फर्म सिनो हिद्रो की चीनी बैंकों से प्राप्त किए गए वित्त-पोषण के माध्यम से कोको कोड़ा सिन्क्ल्येनर जल-विद्युत संयंत्र के निवेश के लिए 85 प्रतिशत तक स्व-वित्त पोषण करने में योग्यता ने इस कंपनी को स्थानीय भागीदार की अपेक्षा को पार किया तथा एक्वाडोरियन सरकार से 1.7 बिलियन डॉलर ऋण प्राप्त कर लिया। हालांकि चीनी निवेश के परिणामस्वरूप लातिन अमेरिका

में सुधार आया था, लेकिन यह स्थानीय अपेक्षाओं की तुलना में कम रहा जिन्होंने ऐसे निवेश के व्यापक आधार की आशा की थी, जो खनन और कृषि क्षेत्रों से परे होता तथा दीर्घकालिक आर्थिक विकास के अनुसरण में अन्य क्षेत्रों की ओर होता। संसाधन अर्जन निवेश के अतिरिक्त, चीन की फर्में क्षेत्र में उनके प्रचालनों का बाजार पहुंच निवेश के माध्यम से विस्तार करना भी आरंभ कर रही हैं। उदाहरण के लिए, चीन के एक अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता चेरी ने 2007 में उरुग्वे में संयंत्रों की स्थापना करके तथा 2009 और 2010 में ब्राजील में डीलरशिप के माध्यम से लातिन अमेरिका में निवेश किया था। इन निवेशों के माध्यम से चेरी ने स्वयं को विश्व के चौथे विशाल ऑटोमोबाइल बाजार ब्राजील में एक अग्रणी प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित कर लिया है। इसी प्रकार, लेनोवो ने कम्प्यूटरों का निर्माण करने के लिए मेक्सिको में 40 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया है जिसका उद्देश्य उत्तरी और दक्षिण अमेरिकी बाजारों में पैठ बनाना है।

लातिन अमेरिकियों के लिए चीन के उदय की विवक्षाएं एक दीर्घकालिक वैश्विक ढांचे के भीतर समझी जा सकती हैं। चीन का अभ्युदय उन तरीकों का केवल एक पहलू है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं की त्वरित वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था और लातिन अमेरिका की संभावनाओं का पुनर्निर्माण कर रही है। पहले ही, खरीददारी की शक्ति में असमानता के संदर्भ में विश्व की विशालतम अर्थव्यवस्थाओं में से चार अर्थव्यवस्थाएं- ब्राजील, रूस, भारत और चीन विकासशील देश हैं। यदि अनुमानों पर विश्वास करें, तो मेक्सिको 2030 तक 'विग सेवेन' के समूह में शामिल हो जाएगा, जब तब अमेरिका शीर्ष सात विशालतम अर्थव्यवस्थाओं में अकेला विकसित देश बना रहेगा। चीन के अतिरिक्त उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का उदय लातिन अमेरिका देशों के लिए पर्याप्त अवसरों का सृजन करेगा। आज, लातिन अमेरिका का लगभग 40 प्रतिशत निर्यात चीन सहित अन्य विकासशीलदेशों में जाता है; यह आंकड़ा उस समय परिवर्तितहो जाएगा जब विश्व के निर्यात में विकासशीलदेशों का हिस्सा दुगने से अधिक हो जाएगा, अर्थात् 2010 में 30 प्रतिशत से 2050 में 69 प्रतिशत। इसके अलावा, क्षेत्रीय शक्तियों ब्राजील और मेक्सिको तथा उनकी बुर्जवावादी मध्यम वर्ग, अन्य लातिन अमेरिका अर्थव्यवस्थाओं के लिएएक वरदान सिद्ध हो सकता है। वस्तुत: ब्राजील अंतराक्षेत्रीय निर्यातों के कुल योग में पहले ही एक-चौथाई भाग का योगदान देता है।

विकासशील विश्व का उदय तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं की कमजोरियां;

संयुक्त राष्ट्र में ऋण-संकट तथा बढ़ती हुई आर्थिक लड़खड़ाहट: यूरोजोन का वित्तीय पतन तथा जापान में राजवित्तीय और जनसांख्यिकीय संकट ने पहले ही अत्यंत भिन्न आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कर दिया जो इस प्रकार की है, जिसमें विशाल नए बाजारों और प्रतिस्पर्धा के नए स्रोतों का उदय होगा तथा जो शक्ति और प्रभाव के संदर्भ में अत्यंत व्यापक रूप से विभाजित होगा। चीन के उदय तथा विश्व के आर्थिक गुरुत्वाकर्षण केन्द्र के पूर्व और दक्षिण की ओर तेजी से होने वाले बदलाव ने लातिन अमेरिका के लिए आर्थिक नीति से संबंधित कम-से-कम तीन आयाम प्रस्तुत किए हैं, जिनका उसके द्वारा समाधान किया जाना है : तुलनात्मक लाभ, आर्थिक राजनयिकता के लिए प्राथमिकताएं तथा वैश्विक प्रणाली में क्षेत्र की भूमिका।

लोकप्रिय छवि के विपरीत, लातिन अमेरिकी पण्य निर्यातक इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि चीन और तुलनात्मक रूप से निर्धन देश हमेशा के लिए पण्यों के मूल्य में उछाल आने से अप्रभावित रहेंगे; अत: उनकी अर्थव्यवस्थाओं का विविधीकरण एक चुनौती बना हुआ है। चूंकि लगभग समस्त पण्यों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति अंतत: आपूर्ति में संवर्धित निवेशों द्वारा तथा प्रौद्योगिकीय अभिनवता द्वारा की जानी होती है, जिससे उत्पादन लागतों में कमी आती है और नए विकल्प विकसित होते हैं, जैसा कि ऐतिहासिक दृष्टि से होता रहा है। इसके अतिरिक्त, जैसे-जैसे रूस, इंडोनेशिया, अफ्रीका और अन्य प्राकृतिक संसाधन निर्यातकों की व्यापार स्थितियों में सुधार होगा, उसके साथ ही उनकी पण्यों के निर्यात की क्षमता में भी सुधार आएगा। अंत: पण्यों के लिए मांग को आय में वृद्धि तथा अभिनवता द्वारा सेवाओं और विनिर्माताओं को होने वाले स्वाभाविक रूपांतरण द्वारा रोक लिया जाएगा, जिससे पण्य उपयोग में अपव्यय और तीव्रता में कमी आएगी। लातिन अमेरिकी संसाधन-आधारित अर्थव्यवस्थाओं को कभी-न-कभी विनिर्माताओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उनकी क्षमता को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता होगी जिसकी मांग में कमी आएगी, जैसे मध्यम वर्गीय बुर्जवा देशों में तथा अन्य उभरते हुए बाजारों में देखने को मिलता है। वर्तमान में, लातिन अमेरिका से चीन को जाने वाले निर्यात में से 90 प्रतिशत भाग खनन और कृषि का है। हालांकि क्षेत्र के व्यापार की शर्तों में सुधार किया गया है, जिसमें 1995 और 2001 के बीच 0.5 प्रतिशत की तुलना में 2002 और 2010 के बीच लगभग 4 प्रतिशत का सुधार हुआ है, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हाल की अनुकूल प्रवृत्तियां अनिश्चितकाल तक जारी रहेंगी। उभरती हुई शक्तियों के उदय द्वारा वैश्विक मांग और

आपूर्ति में कारित किए गए व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनों तथा पण्यों के मूल्यों का पूर्वानुमान लगाने में विद्‌यमान नैसर्गिक अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए लातिन अमेरिका की विकास रणीनति अनेक सत्याभासी परिदृश्यों का सामना करने के लिए अत्यंत ठोस होनी चाहिए। ऐसी नीतियों, जो ऐसी रणनीतिक को अपना सकती है, के उदाहरणों में शामिल है - शिक्षा में निवेश, शासन का सुदृढ़ीकरण, व्यापार परिवेश में सुधार तथा अभिनवता के लिए क्षमता में संवर्धन करना।

हालांकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के एक बड़े भाग में आने वाले दशकों में गिरावट आने की संभावना है, फिर भी अमेरिका के 2050 में भी लातिन अमेरिका के निर्यातों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बने रहने की पूर्ण संभावना है। इसी प्रकार, व्यापार और निवेश के संदर्भ में, वैयक्तिक युरोपीय अर्थव्यवस्थाओं का महत्व भी समय के साथ कम होगा; लेकिन यूरोपीय संघ, एक व्यापार धड़े के रूप में, क्षेत्र में प्रमुख भागीदारों के मध्य बना रहेगा। अत: चीन, भारत, रूस और इंडोनेशिया के प्रति उनकी आर्थिक राजनयिकता का पुन: अभिमुखीकरण करने की आवश्यकता है, जिसमें व्यापार और निवेश करारों को प्रोत्साहित करना भी शामिल है, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र के साथ उसके संबंध निर्णायक बने रहेंगे। और जैसे-जैसे लातिन अमेरिका अर्थव्यवस्थाएं समृद्‌ध तथा अधिक विविधतापूर्ण बनेंगी, उनके लिए क्षेत्रीय एकीकरण को सुदृढ़ बनाने के प्रमुख अवसर उत्पन्न होते रहेंगे, विशेष रूप से जैसे ब्राजील और मेक्सिको विश्व की दो विशालतम अर्थव्यवस्थाएं बनने की राह पर हैं।

अपनी ओर से, लातिन अमेरिकी देश विश्व के मानचित्र पर अधिक प्रभावशाली बन रहे हैं। ब्राजील और मेक्सिको पहले ही जी-20 में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं जो समूचे विश्व में आर्थिक निर्णय लेने वाला नया शीर्ष मंच है जिसका अर्जेंटीना भी सदस्य है। परंतु जैसे-जैसे उनकी आर्थिक शक्ति निरंतर बढ़ती जाएगी, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को रूप प्रदान करने और उसमें अपना योगदान देने के लिए अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करना होगा। इन देशों को इस संबंध में अपने स्वयं के दृष्टिकोण को परिभाषित करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार वैश्विक व्यापार प्रणाली, वित्तीय विनियम, अंतरण नीतियां, विकास सहायता और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले प्रयासों को तैयार किया जाना चाहिए। विभिन्न देश जैसे ब्राजील (और चीन एवं भारत) कभी-कभी स्वयं को विकसित होते विश्व के नेताओं तथा विकसित देशों के विरोध में गरीबों की आवाज उठाने वालों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन, जैसे-जैसे विकासशील

अर्थव्यवस्थाएं अधिक विशाल होंगी और सर्वाधिक शक्तिशाली बनेंगी, उन्हें समान मानसिकता वाले देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए विवश होना ही पड़ेगा चाहे वे निर्धन हों या समृद्ध, यदि वे अपने हितों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करना चाहते हैं।

लातिन अमेरिका को पारंपरिक रूप से अमेरिका के प्रांगण के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, जो ऐस धारणा है, जो 1828के मोनरो सिद्धांत के तैयार और घोषित किए जाने के समय से विद्यमान है तथा जिसे क्षेत्र की राजनीति और समाजों पर वाशिंगटन के शताब्दियों से डाले जा रहे प्रभाव के कारण अंततः बल प्राप्त हुआ। द्विध्रुवीय शीत युद्ध के दौरान, अमेरिका पर अनेक तानाशाहीपूर्ण और प्राधिकारपूर्ण प्रणालियों को पोषित करने, इस प्रक्रिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने और साथ ही अनुचित प्रकार से सज्जित आर्थिक स्पेस पर विवादास्पद नव-उदारवादी आर्थिक सुधार अधिरोपित और उन्हें ग्रहण करने के आरोप लगते रहे। अमेरिका लातिन अमेरिका का विशालतम सैन्य और आर्थिक भागीदार बना रहा तथा यह संबंध लंबे समय तक कायम रहा। अमेरिकी सॉफ्ट पावर, हालांकि हाल के वर्षों में अनेक स्थानों पर उसका विरोध भी हुआ है, विभिन्न तरीकों से क्षेत्र में अभी भी प्रचालन करती है तथा सामाजिक चेतना पर प्रभाव रखती है। बीजिंग का क्षेत्र में वास्तविक अमेरिकी शक्ति के संदर्भ में कोई भ्रम नहीं है और न ही यह लातिन अमेरिका में वाशिगंटन के साथ किसी सैन्य विरोध में उलझने का इच्छुक है। बीजिंग द्वारा मुख्य बल अनेक लातिन अमेरिका देशों के साथ बहुआयामी संबंध स्थापित करके वाशिंगटन को पर्याप्त रूप से रोकने तथा इन संबंधों को दक्षिण-दक्षिण सहयोग के नारे लोकतांत्रीकरण तथा विश्व व्यवस्था के बहुलवाद आदि को रेखांकित करने के लिए आधार के रूप में प्रयोग करने पर प्रदान किया गया है।

सैद्धांतिक संबंध, जिसका अनेक लातिन अमेरिका देशों में वामपंथी पीआरसी तथा वामपंथी अथवा वामोन्मुखी नेताओं के बीच उल्लेख किया जाता है, ऐसे संबंधों का निर्माण करने के लिए एक सुविधाजनक जरिया है, तथा यह किसी भी प्रकार की मतग्राही मैत्री की ओर संकेत नहीं करता है। जहां तक लातिन अमेरिका का संबंध है, इसमें अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के संबंध को तोड़ने तथा गतिशील और आर्थिक रूप से समृद्ध एशिया-प्रशांत में स्थायी भागीदारी का निर्माण करते हुए इसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकता का वैविध्यीकरण करते हुए, बीजिंग के साथ भी संबंध स्थापित करते हुए, राजनीतिक हितधारकों की परिकल्पना की गई है चाहे यह चीन, जापान, दक्षिण कोरिया,

भारत या कोई अन्य देश हो। तथापि, व्यावहारिकता समस्त संबंधित प्रतिरोधियों के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है, वाशिंगटन ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई राजनीतिक और आर्थिक उपस्थिति पर संवेदनशीलता व्यक्त की है, हालांकि वह इसकी सुदृढ़ स्थिति को देखते हुए अनावश्यकरूप से चिंतित नहीं है, बीजिंग वाशिंगटन की अजेय प्राधिकारपूर्ण उपस्थिति को समझता है तथा वह अमेरिकी रणनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए ठोस उपाय करने पर वरीयता देता है, तथा लातिन अमेरिका एक को दूसरे के विरुद्ध प्रयोग करना और संबंधों से इष्टतम लाभ उठाना सुविधाजनकसमझता है। उदाहरण के लिए वेनेजुएला के ह्यूगो चावेज ने अपने अमेरिका विरोधी आडम्बरपूर्ण प्रचार को बल प्रदान करने के लिए बीजिंग के साथ उसकी मित्रता का जोर-शोर से प्रचार किया था; फिर भी वह वाशिंगटन के लिए अपनी तेल आपूतियों को खतरे न डालते हुए पर्याप्त व्यावहारिक बना हुआ है, यहां तक कि वह बीजिंग तथा अन्य राजधानियों को उसके वैश्विक हाइड्रोकार्बन निर्यातों को विविधतापूर्ण बनाने के लिए बीजिंग की खुशामद करता है।

लातिन अमेरिका में पेट्रो-राजनीति और बदलते शक्ति संबंध

क्षेत्र में देशों के बीच अनेक तनाव विद्यमान है, जब हम ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा बाजारों की बात करते हैं। ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए अमेरिका का जोर तथा लातिन अमेरिका की संवेदनशीलता और प्रतिरोध का बल इसे एक समस्याग्रस्त सम्मिश्रण प्रदान करता है, फिर भी अपने मतभेदों के बावजूद वेनेजुएला अपने तेल आयातों के लगभग 15 प्रतिशत भाग की सतत रूप से अमेरिका को आपूर्ति करना जारी रखे हुए है, जबकि कैरीबियाई राष्ट्रों ने इससे पर्याप्त लाभ उठाया है, क्योंकि उन्हें रियायती दल पर तेल की आपूर्ति करने के लिए कैराकास की संधि में उपबंध दिया गया है। परंतु लातिन अमेरिका और विशेष रूप से दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच इस बात को लेकर भी मतभेद विद्यमान है कि ऊर्जा आपूर्ति और मांग के साथ श्रेष्ठ सौदा किस प्रकार किया जाए। क्षेत्र तेजी से विकास करने वाली तथा सर्वाधिक गतिशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में एक, चिली के पास कोई तेल और/अथवा गैस आपूर्ति नहीं है, जबकि इसे पड़ोसी देशों के पास पर्याप्त गैस है। फिर भी, बोलीविया चिली को गैस बेचने से इंकार करता है तथा इस बात के संकेत हैं कि पेरू भी ऐसा ही कर सकता है तथा अर्जेंटीना, जिसकी बढ़ती हुई घरेलू मांग के लिए गैस आपूर्ति में कमी होती जा रही है, चिली के साथ विद्यमान संविदा का उल्लंघन कर रहा है तथा अपनी आपूर्तियों में कमी कर रहा है।

दूसरी ओर, ब्राजील की प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्रों की हालिया खोज के फलस्वरूप, जिसमें उस देश को एक प्रमुख तेल उत्पादक बना देने की क्षमता है, क्षेत्र की विडंबना रेखांकित हुई है, जो ऊर्जा में तो आत्मनिर्भर बन सकता है, परंतु यह अपने सभी लक्ष्यों को एक साथ नहीं रख सकता है अर्थात् अपनी स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति करना और समस्त शामिल देशों के लिए लागतों के परिणामी अवसरों का लाभ उठाना। किसी भी स्थिति में, ब्राजील इस विशेष मुद्दे पर अग्रणी है, जिसमें उसकी सरकार द्वारा स्वामित्व वाली परंतु सरकार द्वारा प्रोत्साहित कंपनी पेट्रोब्रास भी शामिल है, जो बेहतर रूप से प्रबंधित है और संभावित नए क्षेत्रों की तलाश करने और उनमें निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी सृजित करने में समर्थ है। इसकी कड़ी प्रतिस्पर्धा में मेक्सिको की तेल कंपनी पेमेक्स नौकरशाही के नियंत्रणों तथा मेक्सिको सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संदर्भ में गतिरोधों का सामना कर रही है, जो अपने राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत भाग पेमेक्स से प्राप्त करती है, तथा इसके पास मेक्सिको की खाड़ी में आगे अन्वेषण करने के लिए इसकी निधियों के विशाल भाग को आबंटित करने हेतु कम गुंजाइश है। अपनी ऊर्जा नीतियों का पूर्वानुमान लगाने के प्रमाण के रूप में, ब्राजील अपने जैव-ईंधनों और चीनी-आधारित एथनोल (मक्का-आधारित ईंधन की तुलना में ईंधन का एक अधिक कार्यकुशल स्रोत जिसका प्रयोग अमेरिका में किया जाता है) के विकास में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में भी अग्रणी है, जो एक ऐसा उत्कृष्ट कार्यक्रम है जिसके शुरुआत अस्सी के दशक के प्रारंभ में हुई थी तथा यह आज ऐसी फसलों के लिए ब्राजील की कृषि-योग्य भूमि की पर्याप्त मात्रा को ध्यान में रखते हुए फल-फूल रहा है।

अनेक तरीकों से, ऊर्जा विद्युत के वितरण को परिवर्तित करने के लिए साधन के साथ समकालीन अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा के मुख्य संघटक के रूप में उभरकर सामने आई है; तथा यह पराराष्ट्रीय निगमों से दूर है, जिनके हाथों में अधिकाधिक लाभदायक स्थितियां हैं जब इस एजेंडा के मुख्य क्रियान्वयनकर्ता ऐसे राष्ट्र-राज्य के प्रति वैश्वीकृत हो जाते हैं; जिनका हस्तांतरण प्रायः हुआ करता था, परंतु जो प्रतिस्पर्धा से बाहर जाने से हठपूर्वक इंकार कर देते थे। चूंकि परिभाषा के अनुसार ऊर्जा स्रोत माल और सेवाओं के नियमित उत्पादन की तुलना में विशेष भू-भागों में पाए जाते हैं, जिन्हें एक देश से दूसरे की ओर आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है, वे संप्रभु राज्यों के नियंत्रण के अंतर्गत आसानी से आ जाते हैं। पूर्व में, तेल और गैस कंपनियां एंक्लेवों के

रूप में विकसित हुईं, जिससे उन्होंने उन देशों की जनता को कम लाभ प्रदान किया जिनमें उन्हें प्रचालित किया गया था, अत: उससे काफी दुर्भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार, यह संयोग नहीं है कि संभवत: आज दक्षिण अमेरिका में तीन सर्वाधिक उग्रवादी वाम-राष्ट्रवादी सरकारें जिनमें ह्यूगो चावेज के अंतर्गत वेनेजुएला, एवोमोरालेज़ के अंतर्गत बोलीविया तथा राफेल कोरिया के अंतर्गत एक्वाडोर शामिल हैं, तेल और गैस समृद्ध राज्यों को प्रोत्साहन देती पाई जाती है, जिसने इस संसाधनों की प्राप्ति और उनकी जनता को उनसे प्राप्त लाभों को पहुंचाने की चुनौतियों को सफल बनाया है जो उनके लिए प्रथम प्राथमिकताभी है। तथाकथित संसाधन-राष्ट्रवादिता एक यादृच्छिक प्रक्रिया नहीं है, यह ऐसी विनिर्दिष्ट परिस्थितियोंसे उत्पन्न होती है जो इसे परिपक्व बनाती है और विकास को भी अनुमति प्रदान करती है। दक्षिण अमेरिका में, ये एंडियन राष्ट्र ही हैं जिन्हें तेजी से परिवर्तित विश्व अर्थव्यवस्था में मांगों को अनुकूल बनाने में विशेष कठिनाई होती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि अब उन कुछ पण्यों, जिनमें उनके पास प्रचुरता है, के लिए मांग बढ़ती जा रही है तथा वे उसमें से अधिक मांगों का वैधता के साथ पूर्ति करना चाहते हैं।

यह कहा जा सकता है कि लातिन अमेरिका परिवर्तित होते गठबंधनों की अवधि से गुजर रहा है जिसके अंतर्गत नए-नए रणनीतिक नेटवर्कों का सृजन हो रहा है तथा विद्यमान सहयोग संरचनाओं का आशोधन हो रहा है। यह प्रक्रिया बदलते हुए आर्थिक और सुदृढ़ संसाधनों को तथा आर्थिक और विदेश नीति के नए दृष्टिकोणों के साथ राजनीतिज्ञों के निर्वाचन को प्रतिबिंबित करती है। यह कहानी नब्बे के दशक में वेनेजुएला में ह्योग चावेज के साथ प्रारंभ होती है। उनके राष्ट्रपति पद के प्रारंभ में लातिन अमेरिकी बोलिवियाईआंदोलन का विचार अत्यंत कष्ट-कल्पित प्रतीत होता था और हर स्थिति में, यह वास्तविक राजनीति के तुलना में अधिक आडम्बरपूर्ण थी। तथापि, उनके दूसरे कार्यकाल में, नई शताब्दी के प्रथम दशक में पण्य मूल्यों में वृद्धि द्वारा तेल राजस्व में संवर्धन तथा बोलीविया, एक्वाडोर और निकारागुआ में 'वामपंथी' सरकारों के संगठन के साथ, उनकी अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं और क्षेत्र में स्थिति में संवृद्धि हुई। तथापि, उनके लिए बेहतर समाचार यह था कि लातिन अमेरिका में विकास की दर 4-5 प्रतिशत की परिधि में सौम्य हो रही हैं हालांकि उन्होंने, विशेष रूप से यूरोजोन में पश्चिमी आर्थिक और वित्तीय संकट की हानिकर विवक्षाओं को निवारित करने में उल्लेखनीय प्रतिरोध दिखाया।इसका आशाजनक दूसरा पक्ष यह है कि लातिन अमेरिका

में आय का वितरण अत्यंत सौम्यता के साथ सुधर रहा है तथा हालांकि, गरीबी की दर अधिक है, वह सुधार के निश्चयात्मक संकेत दर्शा रही है।

जैसा कि हाल के वर्षों में हुए घटनाक्रमों ने दर्शाया है, ऊर्जा लातिन अमेरिकी राजनीति में एक मुख्य विशेषता बन गई है। लातिन अमेरिकी पेट्रो-राजनीति पर चिली के राजनीतिक वैज्ञानिक गेनारो एरिएगाडा के सारगर्भित विश्लेषण में वर्णित तथ्य के अनुसार "तेल और गैस आपूर्तियों तथा परिवहन नेटवर्कों पर संभावित विरोधाभास अब मुख्य भू-राजनीतिक मुद्दे बन गए हैं.....जैसे-जैसे नए भण्डारों की खोज हो रही है तथा पुराने भण्डार समाप्त हो रहे हैं, राज्यों के मध्य शक्ति का संतुलन उत्पन्न हो रहा है।" यह वर्णित करता है कि क्यों गैस-समृद्ध बोलीविया जिसे पहले इस क्षेत्र में निर्धनतम देश माना जाता था और जो निरंतर ही विदेशी सहायता पर आश्रित रहा था, आज किस प्रकार पूर्व की तुलना में लातिन अमेरिकी राजनीति में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश बन गया है। स्पष्टतः बोलते हुए, तेल निर्यात और उससे उद्भूत होने वाला राजस्व वेनेजुएला विदेश नीति के सर्वाधिक पसंदीदा अवयव हैं। उन्होंने एक सुदृढ़ वेनुजुएला उत्पन्न किया है जो साथी दक्षिण अमेरिकी देशों के लिए एक आश्चर्य की भांति है, जिसने बोलीविया और अर्जेंटीना को भागीदारों के रूप में लेते हुए एक क्षेत्रीय 'गैस उत्पादक ओपेक' की स्थापना करने का प्रस्ताव किया जिसे आर्गेनिजासिओन डी पेसे प्रोडक्टर्स ये एक्सपोर्टाडेरेस दी गैस डी सुरामेअरिका (ओपीपीईजीएसयूआर) कहा जाएगा। वहीं, मेक्सिको अपने तेल भण्डारों में होने वाली कमी से जूझ रहा है। यह मध्य अमेरिका तथा कैरिबियाई क्षेत्र में वेनेजुएला के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसे कठिनाई प्रदान करता है। अपनी ओर से, ब्राजील लातिन अमेरिका में वेनेजुएला के प्रभाव का सामना करने के लिए बायो-डीजल और एथनॉल पर विश्वास कर रहा है। न केवल ब्राजील बल्कि एर्जेंटीना और चिली भी अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ऊर्जा आयातों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा के विकल्प पर निरंतर विचार कर रहे हैं (जिनमें लातिन अमेरिकी पड़ोसी देश से आने वाला आयात भी शामिल है)। मध्यम संदर्भ में, ये घटनाक्रम लातिन अमेरिका में राजनीतिक एजेंडा में परमाणु प्रचुरोद्भवन के मुद्दे को वापस ला सकते हैं।

दूसरी ओर, ऊर्जा एक लाभप्रद अवयव है तथा लातिन अमेरिकी राजनीति में एक ऊर्जा संसाधन है। पिछले वर्ष किए गए एक सर्वेक्षण में, तीन-चौथाई लातिन अमेरिकियों ने मतदान किया था, तथा यह उत्सुकता बनी हुई थी कि ऊर्जा संसाधनों के

लिए प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूपअधिक विवाद उत्पन्न होगा तथा यह अन्य देशों के बीच भी फैल सकता है। दूसरी ओर ऊर्जा संसाधन ऐसे क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बन हुए हैं, जहां अन्य आर्थिक संबंध प्राय: इतने निश्चयात्मक नहीं है, जो आर्थिक एकीकरणपरियोजनाओंके लिए पर्याप्त बल प्रदान कर सकें। अप्रैल, 2007के दौरान वेनेजुएला के मार्गारिटा द्वीप में आयोजित प्रथम दक्षिण अमेरिकी ऊर्जा शिखर-सम्मेलन (दक्षिण अमेरिकी समुदायों के राष्ट्रों के ऊपर ढांचे के भीतर आयोजित) ने ऊपर उल्लिखित दोनों प्रवृत्तियों के लिए एक बेहतर परिकल्पना गठित की है। शिखर-सम्मेलन में, पेरू, सूरीनाम और उरुग्वे को छोड़कर सभी दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रपतियोंने भाग लिया, जिनका नेतृत्व उनके विदेश मंत्रियों अथवा उपराष्ट्रपतियोंद्वारा किया गया था। चर्चा किए गए मुद्दों में से, क्षेत्र में एथनॉल ईंधन का उत्पादन भी शामिल था जिस पर देशों के विचार भिन्न-भिन्न थे। यह सहमति बनी कि 12 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की अध्यक्षता में दक्षिण अमेरिकी ऊर्जा परिषद् (एसएईसी) का गठन किया जाए जो भावी दक्षिण अमेरिकी ऊर्जा संधि (एसएईसी) का गठन किया जाए जो भावी दक्षिण अमेरिकी ऊर्जा संधि (एसएईटी) के संभावनाओं पर विचार करते हुए ऊर्जा नीति को समन्वित करेगी।

शिखर -सम्मेलन के समक्ष, शावेज और फिडेलकास्ट्रो ने ब्राजील और अमेरिका की संयुक्त पहल की निंदा की जिसका उद्देश्य लातिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में एथानॉल और अन्य जैविक-ईंधनों के उत्पादन और प्रयोग को प्रोत्साहित करना था। जबकि शावेज की आलोचना इस संकट पर केन्द्रित थी कि जैविक-ईंधनों (विशेष रूप से मक्का से) का उत्पादन निर्धनों के लिए खाद्य मदों के मूल्यों में वृद्धि करेगा, जो ऐसी आशंका थी जिसकी कुछ क्षेत्रों द्वारा साझा किया गया था तथा उनका वास्तविक लक्ष्य वेनेजुएलाई पेट्रो-राजनीति का विरोध करने के लिए एक उपकरण के रूप में एथानॉल का प्रयोग करने की ब्राजील की रणनीति पर केन्द्रित था तथा अमेरिका के साथ साझे आधार का पता लगाना था। हालांकि, अंतत: वेनेजुलाई सरकार को प्रतिक्रिया देनी पड़ी क्योंकि जैविक-ईंधन अनेक लातिन अमेरिकी देशों, विशेष रूप से वे जिनके पास पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस भण्डार नहीं है, के लिए एक आकर्षक विकल्प हैं। अत: ऊर्जा शिखर-सम्मेलन की अंतिम घोषणा में दोनों बातें शामिल थीं। पेट्रोलियम क्षेत्र में अधिक गहन सहयोग तथानवीकरणीय ऊर्जाओं और जैविक ईंधनों के संवर्धन की घोषणा। सदस्यों ने प्रत्येक देश के ऊर्जा मंत्रियों को सहयोजित करते हुए दक्षिण अमेरिकी ऊर्जा

परिषद का सृजन भी किया जिसे एक साझी रणनीति और कार्य-योजना को विकसित करना था तथा भावी दक्षिण अमेरिकी ऊर्जा संधि (एसएईटी) की संभावना का मुद्दा भी इसमें उठाया गया।

वैश्विक क्षेत्र में लातिन अमेरिका

यह तथ्य स्मरण करना उल्लेखनीय है कि लातिन अमेरिका को भू-राजनीतिक संदर्भ में पारंपरिक रूप से पश्च-भूमिका के निर्वाहक के रूप में ही माना जाता रहा है। इसके असंबद्ध भौगोलिक निर्देशांकों, जो दो अति विस्तारित महासागरीय पिंडों पर फैले हुए हैं, के फलस्वरूप इसकी उपेक्षा की गई है अथवा इसे नजरअंदाज किया गया है, फिर भी इसके प्रति भेदभाव और उस सरसरी उपेक्षा का सामना करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया है। इसके अलावा, इक्कीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान क्षेत्र में आशाजनक विकास दर्ज करने के बावजूद, जो ऐसा समय था जब पश्चिमी ओईसीडी अर्थव्यस्थाएं या तो लड़खड़ा रही थीं अथवा रुग्ण थीं, 'खोए महाद्वीप' अथवा 'वैश्वीकरण के पराजित महाद्वीप' के रूप में लातिन अमेरिका की अप्रष्ठित विशेषताएं सर्वव्यापी रही हैं। पिछले दो दशकों के दौरान लातिन अमेरिका गहन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों से गुजरा है। यह क्षेत्र अब लोकप्रियवादिता अथवा आर्थिक कुप्रबंधन का पर्याय नहीं रह गया है तथा यह लोकतंत्र की कमी के कारण क्षेत्र की पारंपरिक समझ अथवा अवरूद्ध आर्थिक विकास और सामाजिक विदारणों द्वारा विशेषीकृत भी नहीं है।

जैसे-जैसे विश्व का गुरुत्वाकर्षक पूर्व से दक्षिण की ओर जा रहा है तथा उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, वैश्विक निगम अब अधिक समय तक लातिन अमेरिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं अथवा वे ऐसा अपने स्वयं के जोखिम पर ही करेंगे। पिछले वर्षों में लातिन अमेरिकी विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लातिन अमेरिका की भूमिका के संदर्भ में एक अधिक लाभकारी दृष्टिकोण प्रतिपादित करना वस्तुत: संभव है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनीति में परिवर्तनों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर लातिन अमेरिका के लिए नए विदेश नीति विकल्पों को उत्पन्न किया है अथवा उन्हें दीर्घकालिक बनाया है। एक क्षेत्र के रूप में लातिन अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्तमान चक्र के चरम पर है तथा प्राकृतिक संसाधनों और कृषीय कच्ची सामग्रियों के लिए मांग में तेजी उभरती हुई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में विकास की दर को बढ़ा रही है। क्षेत्र के दृष्टिकोण से, इस अपरिवर्तनीय वास्तयविकता ने 'प्रशांत

त्रिकोण (एलए-एशिया-यूएस) के साथ पारंपरिक 'एटलांटिक-त्रिकोण' को संपोषित किया है और उसके अनुपूरण को सुकर बनाया है, जिससे क्षेत्र के भीतर प्रतिरोधियों और अग्रेताओं के लिए अनेक राजनयिक विकल्प देखे जा रहे हैं। जबकि कुछ लोग कह सकते हैं कि एफटीएए परियोजना निष्क्रिय हो गई है, क्षेत्र ने पारस्परिक दृष्टि से लाभप्रद मुक्त व्यापार करार किए हैं तथा व्यवस्थाओं को द्विपक्षीय स्तर तक सहयोजित किया है जिसमें उत्तर का नेतृत्व है, अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध को सुदृढ़ बना रहा है। लातिन अमेरिका के अमेरिका को भेजे जाने वाले उल्लेखनीय तेल निर्यातों के बावजूद, ब्राजील के हाड्रोकार्बन और गैर-पारपंरिक स्रोतों जैसे बायोडीजल और एथनॉल, दोनों में एक अग्रणी पावर हाउस के रूप में उदय के फलस्वरूप वाशिगंटन अब अपनी दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ नया रणनीतिक गठबंधन स्थापित कर रहा है जो ब्रिक्स के भीतर एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

ऐसे समय पर जब दक्षिण सहयोग वस्तुत: अतीत से कतिपय सबक लेते हुए आगे बढ़ रहा है, कुछ लातिन अमेरिकी देशों ने तीसरे विश्व की एकता को पुन: प्रवर्तित कर दिया है जिसमें पश्चिमी गोलार्ध में ईरान जैसे राज्यों का अथक प्रयास भी प्रदर्शित हो रहा है, क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने लातिन अमेरिका में प्रभाव खो दिया है। तेल और संबंध पदार्थों के उच्च मूल्यों ने वेनेजुएला में चावेज जैसे शासनों को सुदृढ़ किया है जिससे वे बाहरी वित्तीय दबावों से बेपरवाह ओर अप्रभावित हो गए हैं जिसमें अर्जेंटीना की सरकार तो आईएमएफ के अपने ऋणों को चुकाने में भी सफल रही है। इसी प्रकार उपमहाद्वीप के दो निर्धनतम देश बोलीविया और एक्वाडोर इस प्रकार से वाशिंगटन की आईएफआई को चुनौती देने में सफल रहे हैं जिसे अस्सी के दशक में अविश्वनीय माना जाता था तथा 'आत्मघाती' करार दिया जाता था। क्षेत्र के शक्तिशाली देश ब्राजील ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक विशेष स्थान हासिल कर लिया है तथा वह उनके मामलों को आगे बढ़ाने में एक वैश्विक भूमिका का निर्वहन कर रहा है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रिया और वैश्विक शासन का लोकतंत्रीकरण और बहुपक्षवाद हो अथवा बहुलवादी मंचों जैसे जी-20, ब्रिक्स, आईबीएसए, बीएएसआईसी और जी-04 आदि में प्रतिभागिता के माध्यम से राष्ट्रों के विकासशील समूह की चिंताओं और हितों को आगे बढ़ाने अथवा उन्हें प्रतिपादित करने का मामला हो। एक दशक से भी अधिक क्षीयमान प्रभाव के उपरांत रूस लातिन अमेरिका में वापसी करने का प्रयास कर रहा है तथा क्षेत्र में

बोलिवायाईभागीदारों के माध्यम से इस क्षेत्र में हथियारों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है। निष्कर्ष के तौर पर लातिन अमेरिका उपेक्षा से प्रशंसा में परिवर्तन की प्रक्रिया में एक प्रकार से सिंड्रेला की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और यहां पर इस राजकुमारी \नुमा देश को प्रलोभित करने के लिए एक से अधिक राजकुमार विद्यमान हैं।

परंतु बदलाता हुआ अंतर्राष्ट्रीय परिवेश लातिन अमेरिकी देशों को भिन्न-भिन्न तरीकों से प्रभावित कर रहा है। जैसे-जैसे बाहरी विकास स्वदेशी प्रक्रियाओं से साथ जुड़ रहा है, लातिन अमेरिका अधिक विविधतापूर्ण बन गया है तथा राजनीतिक दृष्टि से अधिक विखंडित हो गया है। महाद्वीप अनेक विचारों को प्रतिध्वनित करता है जो प्राय: एकमत नहीं होते हैं। यह अस्पष्ट हो जाता है कि लातिन अमेरिका की ओर से कौन प्राधिकारपूर्वक बोल रहा है तथा बाहरी कर्ताओं के लिए लातिन अमेरिका में कौन उपयुक्त संभाषी है। नए अंतर्राष्ट्रीय अंतर्वेश तथा आंतरिक विभाजनों ने लातिन अमेरिका के प्रति यूरोप की विदेश नीति के लिए प्रभाव उत्पन्न किए हैं।

परंतु यह तर्क देना भी एक गलती होगी कि क्षेत्र विकास की ओर जाने वाले एक सुगम मार्ग पर प्रवेश कर चुका है। अनेक समस्याएं अभी बनी हुई हैं जिनमें सामाजिक तनाव, अनुचित राजनीतिक प्रणालियां तथा आर्थिक विकास पर संरचनात्मक बाधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, लातिन अमेरिका संभवत: विश्व का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां सैद्धांतिक दौड़ सक्रिय बनी हुई है। वैकल्पिक विकास मॉडल एक ऐसे प्रकार से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो किसी न किसी रूप में शीत युद्ध की याद दिलाने वाला है जिसमें हथियारों की दौड़ का इसका अनुमान भी शामिल है। जबकि कुछ देश बाजार की प्रमाणिकता और उत्तरदायी सामाजिक नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वहीं अन्य एक नए प्रकार के समाजवाद को घोषित करते हैं। इस बाद वाले समूह में, बाजार-विरोधी नीतियां तथा लोकप्रियवाद प्रभावी राजनीतिकरण नीतियां बन गई है, विशेष रूप से तब, जब उन्हें पण्य निर्यात से प्राप्त होने वाले पर्याप्त राजस्व से जोड़ दिया गया हो। परंतु क्षेत्र में एक साझी संस्कृति से अधिक साझा करता है। विभिन्न कारकों का संयोजन, जिसमें संस्कृति संभवत: सबसे कम महत्वपूर्ण है, के परिणामस्वरूप लातिन अमेरिका की 'विकास समस्या' उत्पन्न हो गई है, जो अनिवार्यत: निम्न आर्थिक विकास और उच्च असमानता का संयोजन है।

तथापि निम्न विकास ही एकमात्र समस्या नहीं है। विश्व के पन्द्रह सबसे असमान देशों में से, कम-से-कम दस लातिन अमेरिका से संबंधित हैं। लातिन अमेरिका की तुलना में, औसत आय गिनी एशिया में आठ बिंदु नीचे है, पूर्वी यूरोप और एशिया में 18 है तथा विकसित देशों में 20 है। अधिक प्रासंगिक तथ्य यह है कि लातिन अमेरिका में असमानता इसके प्रति व्यक्ति जीडीपी द्वारा अनुमानित आंकड़े से अधिक है: गिनी गुणांक प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिए हिसाब में लिए जाने के पश्चात् शेष विश्व की तुलना में लातिन अमेरिका में लगभग 10 बिंदु अधिक है। एक बात पर व्यापक बहस की जाती है कि क्षेत्र इतना असमान कब हो गया। कुछ लेखक जैसे जेफ्री विलियसन, हार्वर्ड विश्वविद्यालय यह मानते हैं कि लातिन अमेरिका में असमानता 1942 के बाद के विजयोपरांत दशकों से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक विश्व के अन्य भागों की तुलना में अधिक नहीं थी। यहां पुन: उन्नीसवीं शताब्दी दोषी प्रतीत होती है, विशेष रूप से स्वतंत्रता के प्रथम दशक। इस तथ्य को प्राय: द्विशतवार्षिकी समारोहों में नजरअंदाज कर दिया गया है जो समूचे महाद्वीप में फिलहाल मनाए जा रहे हैं। आरोपित असमानता की दो शताब्दियां यह सुझाती है कि यह परिवर्तन धीमे होगा और आवश्यक नहीं है कि यह आसान हो।

एक अन्य विशेषता जो पूर्व चर्चा से पर्याप्ततः प्रासंगिक है तथा उससे स्वतंत्र नहीं है, वह पण्यों पर लातिन अमेरिका का अत्यधिक निर्भरता है। जैसाकि विश्व बैंक के आगामी प्रकाशन में वर्णित किया गया है, "लातिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र के आर्थिक इतिहास की भित्तिका इसके पण्यों के रंगों से रंगी हुई है।" इसके विजेताओं को आकर्षित करने वाले सोने और चांदी से लेकर चीनी और काफी बागानों तक, तांबे और कोयले की खानों से लेकर 'काले सोने' तक पण्यों ने क्षेत्र के भाग्य को परिभाषित किया है तथा यह निकट भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। चाहे यह विकास का आंशिक प्रभाव हो, आंशिक कारण हो, समस्याओं पर चर्चा की जानी जारी रहेगी, परंतु व्यवसाय धीरे-धीरे इस दृष्टिकोण की ओर झुक रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का वस्तुत: विकास पर सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए, जब उन्हें उचित रूप से प्रबंधित किया जाए। इस बात में कम ही संदेह है कि ये पण्य पिछले दशक में अभिशाप की तुलना में वरदान अधिक सिद्ध हुए हैं, जो क्ष्रेर में हालिया अनुकूल आर्थिक प्रदर्शन का वर्णन करता है।

पण्यों पर निर्भरता यह वर्णन करती है कि क्यों लातिन अमेरिका चीन की घटनाओं द्वारा इतना प्रभावित होता है। वस्तुत: लातिन अमेरिका में निर्यात मूल्यों

तथा चीन में औद्योगिक उत्पादन के बीच सह-संबंध लगभग 60 प्रतिशत है। चीन पर अत्यधिक निर्भरता के कतिपय जोखिम है, इसलिए नहीं कि चीनी अर्थव्यवस्था अधिक प्रभावी हो सकती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि लातिन अमेरिकी सरकारें चीन के साथ अपने संबंधों में स्वतंत्रता की मात्रा खोती जा रही हैं। ब्यूनर्स आयर्स द्वारा अपनाए गए प्रतिपादन उपायों के प्रत्युत्तर में अर्जेंटीना के सोय के अपने आयात को समाप्त करने की चीन द्वारा दी गई हालिया धमकी उन समस्याओं की ओर इशारा करती है जो आगे आने वाली है। इसके अलावा, लातिन अमेरिकी की सरकारें निरंतर इस बात से अवगत होती जा रही है कि अमेरिकी डॉलर की तुलना में उनकी घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन एक गंभीर समस्या है मुख्यत: इसीलिए क्योंकि चीन की मुद्रा अभिमूल्यित नहीं होती है।

एक अंतिम सामान्यत: जो लातिन अमेरिकी को प्रभावित कर रही है, वह यह तथ्य है कि राजनीतिक प्रणालियां अधिक मुक्त और बहुलवादी हो गई हैं। पिछले दो दशकों के दौरान, अधिकांश देशों ने राजनीतिक प्रतिभागिता और प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिए अपने संविधानों में सुधार किया है जिनमें चीन और ब्राजील (1989); कोलम्बिया (1991); पराग्वे (1992); पेरू (1993); अर्जेंटीना, ग्वाटेमाला और निकारागुआ (1994); वेनेजुएला (1999); एक्वाडोर (2008); और बोलीविया (2009) शामिल है। हालांकि सांस्थानिक प्रदर्शन पर इन सुधारों का प्रभाव विविधतापूर्ण नहीं है, परंतु सामाजिक नीतियां और सामाजिक व्ययों ने समूचे क्षेत्र में प्रचुरता हासिल की है। इसमें सफलताएं प्राप्त हुई हैं, जैसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन दरों में वृद्धि परंतु अनेक समस्याएं विद्यमान रही है जैसे पूर्व-प्राथमिक और माध्यम शिक्षा विशेष रूप से निर्धनों के लिए मैं निम्न शैक्षणिक गुणवत्ता और निम्न नामांकन दर। इसके सकारात्मक पक्ष में, अनेक संख्या में अमेरिकी देशों ने सशर्त नकदी अंतरण (सीसीटी) आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक हस्तक्षेप क्रियान्वित किए जो शेष विश्व के लिए आदर्श के रूप में स्थापित हुए। विद्यमान मूल्यांकन यह सुझाता है कि ये कार्यक्रम, चाहे वे जितने भी छोटे क्यों न हों, निम्न आय वाले कुटुंबों की आय को पुनर्वितरित करने के प्रभावी उपाय हैं जबकि साथ ही साथ उन्होंने मानवीय पूंजी में निवेश के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए हैं।

निष्कर्ष के पौर पर, लातिन अमेरिका एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनता जा रहा है। कुटुबों, फर्मों और सरकारों को पर्याप्त रूप से बल नहीं दिया जा रहा है, जिससे लेहमैन के पतन के उपरांत अत्यंत सीमित संक्रमण का वर्णन किया जा सकता है। यही

बात यूरोप में हालिया घटनाक्रमों पर भी लागू की जा सकती है जो अब तक लातिन अमेरिका संप्रभु और निगमित बंधों पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। इससे यह पता चलता है कि क्षेत्र को अब एक दशक पूर्व की तुलना में एक बेहतर आस्ति वर्ग के रूप में परिकल्पना की जा रही है। तथापि, क्षेत्र के देश आगामी कुछ वर्षों में आर्थिक विकास के विविधतापूर्ण मार्गों का अनुपालन करेंगे। कुछ देश समानता के साथ विकास को मजबूत बनाएंगे तथा कुछ आर्थिक आपदा की ओर आगे बढ़ेंगे, जिससे दीर्घकालिक विरोधाभासोंद्वारा अपनाए गए अल्पकालिकआर्थिक विस्तारों के चक्र को दोहराएंगे जो लातिन अमेरिका के लिए सुविख्यात है।

******

लेखक के बारे में

दत्तेश डी. परुलेकर यूजीसी लातिन अमेरिकी अध्ययन केन्द्र, गोवा विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध और अरब अध्ययन (लातिन अमेरिकी और कैरीबियाई क्षेत्र) के सहायक प्रोफेसर हैं। वे वर्तमान में 'विवादपूर्ण प्रबंध और समाधान' विषय पर अपने डॉक्टोरल शोध कार्य की अंतिम अवस्था पर है जिसमें उनके शोध प्रबंध का शीर्षक है 'शीत-युद्ध के बाद के विश्व में शक्तिशाली मानववाद: नब्बे के दशक में प्रपीड़क मानववाद हस्तक्षेपों का सिद्धांत'। वे फल्ब्राइट फेलो है तथा उन्होंने अपनी पीएच.डी करने के दौरान प्रो. विलियम आई. जार्टमैन के अंतर्गत कंफ्लिक्ट मैजेजमेंट सेंट ऑफ दि स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज, जांस हॉपकिंस यूनीवर्सिटी, वाशिगटन डीसी, यूएसए में क्षेत्रीय शोधकार्य संचालित किया है। उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं - अमेरिकी विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत की विदेश नीति तथा लातिन अमेरिकी और कैरीबियाई (एलएसी) क्षेत्र में राजनीति और शासन आदि।

ISBN 978-93-83445-01-1

विश्वमामलों की भारतीयपरिषद

स्प्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001